वर्ष 12 • अंक 248 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 5 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

प्याज की कच्ची फसल ही काट रहे किसान

सुनील भारती मित्तल पृष्ठ 2

एयरटेल जुटाएगी 300 करोड़ डॉलर

डॉलर रु. 71.50 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 79.20 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38184 ▲ 73 रुपये | सेंसेक्स 40850.30 ▲ 174.80 | निफ्टी 12043.20 ▲ 49.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12089.80 ▲ 46.60 | ब्रेंट क्रूड 61.80 डॉलर ▲ 0.90 डॉलर

एक नज़र

चिदंबरम को 105 दिन बाद मिली जमानत

आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी जिससे 105 दिन की हिरासत के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चिदंबरम उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकते है और वह गवाहों को न तो प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। अदालत ने दो लाख रुपये का निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत के साथ चिदंबरम को रिहा करने का आदेश दिया। पृष्ठ 12

पहले ही दिन 54 फीसदी चढ़ा सीएसबी बैंक का शेयर

सीएसबी बैंक ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते ही धमाकेदार शुरुआत की और इसका शेयर 54 फीसदी उछलकर बंद हुआ। बीएसई पर बैंक का शेयर 195 रुपये के निर्गम मूल्य की तुलना में 45 फीसदी चढ़कर 275 रुपये पर खुला। कारोबार के दौरान एक समय 307 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि कारोबार की समाप्ति पर यह 53.89 फीसदी बढ़त के साथ 300.10 रुपये पर बंद हुआ। सीएसबी बैंक के आईपीओ को पिछले महीने 86.89 गुणा अभिदान मिला था। पृष्ठ 3

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस को 170 गुना बोलियां

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के आईपीओ को बुधवार को अंतिम दिन में अब तक 170 गुना आवेदन मिला है। संस्थागत निवेशकों की ओर से 114 गुना बोलियां मिलीं, वहीं धनाढ्य निवेशक श्रेणी में 486 गुना आवेदन प्राप्त हुए। खुदरा निवेशक श्रेणी में 50 गुना बोलियां मिलीं। 442 करोड़ रुपये के निर्गम के लिए करीब 76,000 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं। आईपीओ का मूल्य दायरा 36-37 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। पृष्ठ 3

जियो के नए टैरिफ प्लान 39 फीसदी तक महंगे

रिलायंस जियो ने बुधवार को अपने नए ऑल इन वन प्लान की घोषणा की। ग्राहकों के लिए 6 दिसंबर से लागू होने वाले ये प्लान पिछले टैरिफ प्लान से 39 प्रतिशत तक महंगे हैं। नए मोबाइल एवं डेटा प्लान के मुताबिक जियो के ग्राहकों को 84 दिन वैधता और 1.5 जीबी प्रति दिन डेटा वाले प्लान के लिए अब 555 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल यह 399 रुपये में उपलब्ध है। 153 रुपये के प्लान के दाम को बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया गया है।

आज का सवाल

क्या डेटा संरक्षण विधेयक से लोगों की निजता होगी सुरक्षित

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या ई-फार्मेसी पर सरकार को जल्द बनाने चाहिए नियम?	हां	90.00%
	नहीं	10.00%

डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी

शीत सत्र में पेश होगा विधेयक, डेटा संग्रहण व प्रसंस्करण में थोड़ी ढील का प्रावधान

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-प्रतीक्षित डेटा सुरक्षा विधेयक पर आज मुहर लगा दी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि विधेयक में पिछले मसौदे में शामिल सभी तरह के व्यक्तिगत डेटा के अनिवार्य संग्रह और इनके प्रसंस्करण की जरूरत से जुड़े प्रावधानों में ढील दी गई है। हालांकि सरकारी सेवाओं की योजना तैयार करने के उद्देश्य से कंपनियों के पास उपलब्ध डेटा के इस्तेमाल का भी प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक में डेटा दो श्रेणियों- संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा- में विभाजित किए गए हैं। संवेदनशील डेटा में पासवर्ड, वित्तीय सूचनाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां, यौन अभिरुचि, शारीरिक जानकारियां, जीन से जुड़ी सूचनाएं, जाति या प्रजाति आदि शामिल हैं। अति महत्त्वपूर्ण जानकारियों की परिभाषा सरकार समय-समय पर तय करती रहेगी।

सभी कंपनियों के लिए लोगों की महत्त्वपूर्ण जानकारियां देश में ही संग्रहित करनी होंगी। हालांकि वे जिस व्यक्ति का डेटा है उसकी इजाजत लेकर विदेश में इन्हें भेज सकती हैं। सूत्र ने कहा कि विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद इनका इस्तेमाल केवल कानून के तहत परिभाषित कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा।

विधेयक में समाहित प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सभी व्यक्गित जानकारियों की एक प्रति रखने को लेकर कुछ रियायत दी गई है। सूत्र ने कहा,'सरकार के पास डेटा संग्राहकों को विशेष उद्देश्यों जैसे सेवाओं में सुधार, नीति निर्धारण, राहत कार्य आदि के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए कह सकती है।'

गैर-व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़े सभी दूसरे पहलुओं का प्रबंधन इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई कंपनी विधेयक में वर्णित प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करती है तो उसे 15 करोड़ रुपये तक या अपने वैश्विक राजस्व का 4 प्रतिशत तक जुर्माना देना होगा। छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए बतौर जुर्माना कंपनी को 5 करोड़ रुपये या वैश्विक राजस्व का 2 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा।

विधेयक के दायरे में सोशल मीडिया कंपनियां भी आएंगी। इन कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं की पहचान का तरीका मुहैया कराना होगा। एक सूत्र ने कहा, 'प्रावधान के तहत किसी सोशल मीडिया कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर को खुद को सत्यापित करने का विकल्प देना होगा।हालांकि यह किसी व्यक्ति का अपना निर्णय होगा कि वह सत्यापित होना चाहता है या नहीं।'

- विधेयक के पिछले मसौदे के कुछ प्रावधानों में ढील दिए जाने के संकेत
- भारत में सभी व्यक्तिगत डेटा की अनिवार्य प्रति रखने संबंधी प्रावधान में ढील
- पिछले एक वर्ष से इस विधेयक पर चल रहा था काम

बॉन्ड ईटीएफ में निवेश को हरी झंडी

सरकार ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) नाम से एक साझा निवेश कोष शुरू करने के प्रस्ताव पर बुधवार को मुहर लगा दी। इसकी यूनिट में निवेश करने वालों की रकम सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संठनों के बॉन्ड में लगाई जाएगी। इस ईटीएफ के नए कोष की पेशकश (एनएफओ) दिसंबर में आने का अनुमान है। भारत बॉन्ड ईटीएफ देश में पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ होगा। पृष्ठ 4

एफऐंडओ में फर्जीवाड़े पर आयकर विभाग सख्त

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

आयकर विभाग ने ऐसे कई ब्रोकरों और निवेशकों के खिलाफ आज कार्रवाई की जो न के बराबर खरीद-बिक्री वाले स्टॉक ऑप्शन में फर्जी तरीके से कारोबार कर रहे थे।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता सहित देश भर में 150 जगहों पर तलाशी और छापेमारी की। घटनाक्रम के जानकार एक कर अधिकारी ने कहा, 'बाजार नियामक से इक्विटी डेरिवेटिव खंड में अनियमितता के संकेत मिलने के बाद हमने इस मामले में जांच शुरू की थी।'

उन्होंने कहा कि ताजा कार्रवाई बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ डेरिवेटिव अनुबंधों की जांच पर आधारित है। सूत्रों ने कहा कि इस जांच के दायरे में 2014 से पिछले पांच साल के दौरान इस खंड में किए गए कारोबार को शामिल किया गया है। जांच अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।

कर विभाग को संदेह है कि ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों और निवेशकों सहित 20,000 इकाइयों ने इसके जरिये करीब 80,000 करोड़ रुपये की कर चोरी की है। इस साल की शुरुआत में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई पर इस तरह स्टॉक ऑप्शन में फर्जी तरीके से कारोबार करने वाली 9 इकाइयों पर 55 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया था। (शेष पृष्ठ 3 पर)

- देश भर में 150 जगहों पर ब्रोकरों, निवेशकों के यहां तलाशी
- 5 लाख रुपये तक शेयर खरीदने वाले निवेशक जांच दायरे में
- पिछले पांच साल के दौरान डेरिवेटिव सौदों की जांच
- आयकर विभाग को करीब 80,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का संदेह

प्रगति मैदान में बनेगा पांच सितारा होटल

बीएस संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में पांच सितारा होटल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान पर भूमि के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी, जहां एक पांच सितारा होटल का निर्माण होगा। इसके साथ ही वहां विश्वस्तरीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य के लिए 3.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को बुधवार को मंजूरी दी। पांच सितारा होटल के विकास और संचालन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम एक विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) का गठन करेंगे। एसपीवी के लिए 611 करोड़ रुपये के मूल्य पर 99 वर्ष के पट्टे के तहत 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन को अधिकृत किया गया है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी होटल बनाने के प्रसताव को मंजूरी
- 99 साल के पट्टे पर दी जाएगी 3.7 एकड़ अतिरिक्त जमीन
- होटल का संचालन करने के लिए आईटीडीसी और आईआरसीटीसी बनाएंगे एसपीवी

कॉलोनियों को नियमित करने का विधेयक पारित

दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा पेश विधेयक को बुधवार को संसद से मंजूरी मिल गई। इन कॉलोनियों में रहने वाले लगभग नौ लाख परिवारों को संपत्ति का मालिकाना हक देने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 को राज्यसभा ने बुधवार को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पिछले सप्ताह पारित कर चुकी है।

दिल्ली में 16 दिसंबर से मुफ्त वाई-फाई

केजरीवाल सरकार ने लंबे इंतजार के बाद मुफ्त वाई-फाई का वादा 16 दिसंबर से पूरा करने का ऐलान किया है। यह ऐलान ऐसे में समय किया गया है, जब देश में दूरसंचार कंपनियों ने मोबाइल प्लान में 40 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। सरकार इस योजना पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर दिल्ली वालों को हर माह 15 जीबी मुफ्त इंटरनेट डेटा देगी। पहले चरण में 100 हॉटस्पॉट कश्मीरी गेट आईएसबीटी, आईटीओ, मंडी हाउस, सराय काले खां, दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टॉप के साथ इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जैसे अहम स्थानों पर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 16 दिसंबर को 100 हॉटस्पॉट और इसके बाद हर सप्ताह 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे और अगले छह महीने में पूरे 11,000 हॉटस्पॉट लग जाएंगे।

कार्वी मामले में बैंकों को सैट से राहत नहीं

प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट) ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के मामले में एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को राहत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। इन ऋणदाताओं ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग द्वारा गिरवी रखे शेयरों को वापस ग्राहकों को स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी थी। सैट ने ऋणदाताओं से 6 दिसंबर तक सेबी के पास नई याचिका दायर करने और नियामक से 12 दिसंबर तक आदेश देने को कहा है। बैंकों का कहना था कि सैट या तो ये प्रतिभूतियां उन्हें वापस दिलाए या एस्क्रो खाते में डाले। सैट ने कहा कि बजाज फाइनैंस की याचिका के मामले में आए आदेश के अलावा इसमें ऋणदाताओं को और राहत नहीं दी जा सकती। *बीएस*

सुंदर पिचाई को अल्फाबेट की कमान

कंपनी के सह-संस्थापकों लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने प्रबंधन से अलग होने का किया निर्णय

एजेंसियां
वाशिंगटन, 4 दिसंबर

गूगल के भारतीय-अमेरिकी मूल के मुख्य कार्याधिकारी सुंदर पिचाई अब इसकी प्रवर्तक कंपनी अल्फाबेट की कमान संभालेंगे। गूगल के सह-संस्थापकों लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने खुद को प्रवर्तक कंपनी अल्फाबेट के सक्रिय प्रबंधन से अलग कर लिया है। अल्फाबेट और गूगल के प्रबंधन में हुए इस फेरबदल से पिचाई दुनिया के सबसे प्रभावशाली कारोबारी दिग्गजों में से एक बन गए हैं।

अल्फाबेट ने मंगलवार को बताया कि पेज मुख्य कार्याधिकारी और और ब्रिन अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। गूगल के मौजूदा मुख्य कार्याधिकारी 47 वर्षीय पिचाई अल्फाबेट की कमान संभालेंगे। यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है जब गूगल को कंपनी व्यापक आकार, सूचनाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा को लेकर कंपनी का रवैया तथा समाज पर संभावित प्रभाव को लेकर जांच के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दोनों सह-संस्थापकों ने एक सार्वजनिक पत्र में कहा कि अब अल्फाबेट अच्छे से स्थापित हो चुकी है और गूगल समेत अन्य सहायक कंपनियां स्वतंत्र तरीके से प्रभावी परिचालन कर रही हैं, ऐसे में यह स्वाभाविक समय है कि प्रबंधन के स्वरूप को सरल बनाया जाए।

उन्होंने कहा, 'हम उन लोगों में कभी नहीं रहे कि जब कंपनी चलाने का बेहतर तरीका उपलब्ध हो, तब भी प्रबंधन में बने रहें। और अब अल्फाबेट तथा गूगल को दो अलग मुख्य कार्याधिकारी के साथ एक अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सुंदर गूगल के साथ अल्फाबेट के भी मुख्य कार्याधिकारी होंगे। वह गूगल का नेतृत्व करेंगे तथा अल्फाबेट के अन्य कारोबार में निवेश का प्रबंधन करेंगे।'

हालांकि दोनों सह-संस्थापक अल्फाबेट के निदेशक मंडल में बने रहेंगे। पिचाई ने कहा कि इस बदलाव से अल्फाबेट की संरचना या उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लिखा, 'मैं गूगल पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहूंगा और साथ ही कंप्यूटिंग के दायरे को बढ़ाने, गूगल को हर किसी के लिए अधिक मददगार बनाने के अपने काम को करता रहूंगा।' पिचाई ने अपने ईमेल में कहा, 'मैं अल्फाबेट और प्रौद्योगिकी के जरिये बड़ी चुनौतियों से निपटने के उसके दीर्घकालिक उद्देश्य को लेकर उत्साहित हूं।'

पिचाई के नेतृत्व की तारीफ करते हुए पेज और ब्रिन ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी सीईओ हर दिन अपने उपभोक्ताओं, साझेदारों और कर्मचारियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रति गहरा जुनून पैदा करते हैं। सह-संस्थापकों ने कहा, 'सुंदर ने अल्फाबेट की स्थापना के वक्त, गूगल के मुख्य कार्याधिकारी रहते हुए और अल्फाबेट के निदेशक मंडल के सदस्य के नाते 15 वर्ष तक हमारे साथ काम किया है। अल्फाबेट की स्थापना के बाद से अब तक हमने किसी और पर इतना भरोसा नहीं किया और उनके अलावा गूगल और अल्फाबेट का भविष्य में कोई इतने अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं कर सकता।'

- पेज और ब्रिन ने खुला पत्र लिखकर इस बारे में दी जानकारी
- दोनों सह-संस्थापक अल्फाबेट के निदेशक मंडल में बने रहेंगे

'मैं अल्फाबेट और प्रौद्योगिकी के जरिये बड़ी चुनौतियों से निपटने के उसके दीर्घकालिक उद्देश्य को लेकर उत्साहित हूं।'

सुंदर पिचाई, सीईओ, गूगल

खबरों में रहे स्टॉक

टाटा मोटर्स

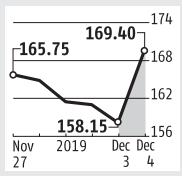

नवंबर में जेएलआर की बिक्री 6.2 फीसदी बढ़ी

₹ 158.15 पिछला बंद भाव
₹ 169.40 आज का बंद भाव
▲ 7.11 %

रिलायंस इंडस्ट्रीज

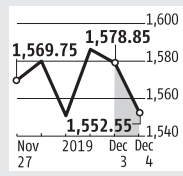

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 1,578.85 पिछला बंद भाव
₹ 1,552.55 आज का बंद भाव
▼ 1.67 %

आईसीआईसीआई बैंक

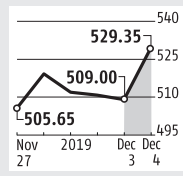

एक दमदार खुदरा सह डिजिटल बैंक बनने की तैयारी

₹ 509.00 पिछला बंद भाव
₹ 529.35 आज का बंद भाव
▲ 4.00 %

उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज

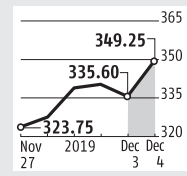

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को मिला 164 गुना अभिदान

₹ 335.60 पिछला बंद भाव
₹ 349.25 आज का बंद भाव
▲ 4.07 %

डिक्सन टेक्नोलॉजिज (इंडिया)

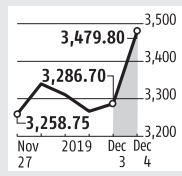

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 3,286.70 पिछला बंद भाव
₹ 3,479.80 आज का बंद भाव
▲ 5.88 %

संक्षेप में

कोका कोला की बॉटलिंग इकाई फ्रैंचाइजी को

शीतल पेय कंपनी कोका कोला भारत में अपने बॉटलिंग कारोबार में फेरबदल किया है। उसने उत्तर भारत में हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज लिमिटेड (एचसीसीबी) के खुद के पेय पदार्थ बॉटलिंग कारोबार को कंपनी के फ्रैंचाइजी भागीदारों को स्थानांतरित करने की घोषणा की है। इस तरह एचसीसीबी उत्तर भारत में बॉटलिंग कारोबार से बाहर निकल रही है। कोका-कोला ने बयान में कहा कि पुनर्गठन के तहत एचसीसीबी उत्तर भारत में चार क्षेत्रों का परिचालन कंपनी के बॉटलिंग भागीदारों को स्थानांतरित कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वह पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में परिचालन जारी रखेगी। बयान में कहा गया है कि इस कदम का मकसद भारत में अधिक मजबूत और अधिक स्थिर स्थानीय कारोबार बनाना है। फिलहाल कोका कोला के बॉटलिंग नेटवर्क में एचसीसीबी सहित कुल 14 कंपनियां शामिल हैं। देशभर में कंपनी के 55 से अधिक बॉटलिंग संयंत्र हैं। *भाषा*

ग्रेग हाइटेनरॉच कॉग्निजेंट के कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी कॉग्निजेंट ने ग्रेग हाइटेनरॉच को कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं डिजिटल प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ब्रायन हंफ्रीज ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए इसकी सूचना दी। हाइटेनरॉच इससे पहले वोडाफोन में कार्यकारी रह चुके हैं। वह वोडाफोन से पहले कैपजेमिनाई में भी 7 साल काम कर चुके हैं। हंफ्रीज ने कहा, मैं ग्रेग के साथ वोडाफोन में काम कर चुका हूं और इस कारण जानता हूं कि वह उपभोक्ता केंद्रित नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हैं जो उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाएं मुहैया कराने और कंपनी को अच्छा परिणाम दिलाने के लिए उत्साहित रहते हैं। *भाषा*

हुंडई के बिक्री, विपणन प्रमुख बने तरुण गर्ग

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने तरुण गर्ग को बिक्री, विपणन एवं सेवा का निदेशक नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि गर्ग ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (लखनऊ) से पढ़ाई की है। उनके पास बिक्री, विपणन, नेटवर्क विकास तथा पुरानी कारों के कारोबार का 25 साल का अनुभव है। गर्ग इससे पहले मारुति सुजूकी इंडिया में विपणन, कलपुर्जे एवं लॉजिस्टिक्स के कार्यकारी निदेशक थे। *भाषा*

एयरटेल जुटाएगी बड़ी रकम

क्यूआईपी के जरिये 3 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी कर रही कंपनी

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

भारती एयरटेल ने बुधवार को पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से तीन अरब डॉलर जुटाने की घोषणा की, जिसका उपयोग मुख्य तौर पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया के कारण केंद्र सरकार को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। कंपनी बोर्ड ने एक या एक से अधिक क्यूआईपी, इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक या निजी पेशकश, अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचरों आदि के माध्यम से दो अरब डॉलर जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

शेयर बाजार को दी गई सूचना में कंपनी ने बताया, 'कंपनी को एक अरब डॉलर विदेशी ऋण के जरिए जुटाने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा वह बिना गारंटी वाले या गारंटी वाले, सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध, विमोच्य गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों या इसी तरह की अन्य प्रतिभूतियों के जरिए भारतीय रुपये में सामूहिक रूप से एक या अधिक किस्तों में एक अरब डॉलर और जुटाएगी।' इसमें कहा गया, दो अरब डॉलर के अलावा कुल एक अरब डॉलर अतिरिक्त जुटाने की भी मंजूरी मिल गई जिससे कुल राशि तीन अरब डॉलर हो गई है।

भारती एयरटेल ने ऐसे समय में वित्तीय राशि जुटाने की घोषणा की है जब कंपनी तो एजीआर बकाया के तौर पर केंद्र सरकार को करीब 43,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं। एयरटेल ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में 23,044 करोड़ रुपये के सकल घाटे की घोषणा की थी। इसके साथ ही कंपनी को एजीआर बकाया के तौर पर इस तिमाही 28,450 करोड़ रुपये भी चुकाने हैं। इस राशि में 6,164 करोड़ रुपये मूल राशि, 12,219 करोड़ रुपये इस राशि पर ब्याज, 3,760 करोड़ रुपये पेनल्टी और 6,307 करोड़ रुपये पेनल्टी पर ब्याज शामिल है। यह राशि अनुमानित आधार पर लाइसेंस शुल्क से संबंधित है।

प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहने के प्रयासों के तहत कंपनी ने एक दिसंबर से प्रीपेड ग्राहकों से जुड़े मोबाइल पैक की कीमतों में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। एयरटेल के नए प्लान में 50 पैसे प्रतिदिन से लेकर 2.85 रुपये रोजाना तक की बढ़ोतरी की गई है जिसमें डेटा और फोन कॉल की सुविधाएं शामिल हैं।

दूरसंचार कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए 24 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एजीआर बकाया के तौर पर कुल 92,641 करोड़ रुपये की वसूली करने की अनुमति केंद्र सरकार को दे दी।

शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को उनकी गणना के लिए गैर-दूरसंचार राजस्व पर विचार करने के बाद पिछले बकाया में से 1.4 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। दूरसंचार कंपनियां बकाया राशि पर ब्याज तथा जुर्माने से छूट और न्यायालय द्वारा निर्धारित तीन महीने की समयसीमा में विस्तार की मांग कर रही हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को 42,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए वार्षिक किस्तों के तौर पर दिए जाने वाले भुगतान पर भी दो वर्ष तक रोक लगाने का विकल्प दिया है।

पूंजी जुटाने की योजना

- कंपनी बोर्ड ने एक या एक से अधिक क्यूआईपी, इक्विटी शेयरों की सार्वजनिक या निजी पेशकश, अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचरों आदि के माध्यम से दो अरब डॉलर जुटाने की मंजूरी
- विदेशी ऋण के जरिए जुटाएगी एक अरब डॉलर की राशि
- बिना गारंटी वाले या गारंटी वाले, गैर सूचीबद्ध, गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों या इसी तरह की अन्य प्रतिभूतियों के जरिए एक अरब डॉलर अतिरिक्त जुटाएगी

एयरटेल की पेशकश पर सीओसी करेगी चर्चा

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

- अनिल अंबानी की कंपनियों के लिए भारती की पेशकश
- भारती एयरटेल ने तीन कंपनियों के लिए की 3,000 करोड़ रुपये की पेशकश

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहीं अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली तीन कंपनियों के लिए भारती एयरटेल ने करीब 3,000 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की पेशकश की है। एयरटेल की बोली एवं अन्य पेशकश पर चर्चा के लिए इन कंपनियों के लेनदारों की समिति की बैठक जल्द होने वाली है। इन तीन कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल शामिल हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस टेलीकॉम के पास स्पेक्ट्रम एवं कुछ अन्य कारोबार हैं जबकि रिलायंस इन्फ्राटेल के पास टावर एवं फाइबर परिसंपत्तियां हैं। इस रकम में बकाया स्पेक्ट्रम भुगतान शामिल नहीं है जिसके लिए उन्हें कई वर्षों तक सरकार को भुगतान करना है।

सूत्रों के अनुसार, भारती ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस टेलीकॉम के लिए करीब 1,050 करोड़ रुपये की पेशकश की है। इनके पास विभिन्न बैंड में करीब 122 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। साथ ही 4जी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल्यवान 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी इनके पास 58 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मौजूद है लेकिन फिलहाल उसका इस्तेमाल रिलायंस जियो 21 सर्किल में स्पेक्ट्रम साझेदारी अनुबंध के तहत कर रही है। इसके अलावा भारती ने रिलायंस इन्फ्राटेल के लिए 1,900 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।

सूत्रों ने बताया कि इस रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल परिचालन लेनदारों के बकाये के भुगतान, कार्यशील पूंजी और कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया की लागत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लेनदारों को करीब 1,750 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

भारती एयरटेल ने इस बाबत जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया।

सूत्रों के अनुसार, रिलायंस जियो ने रिलायंस इन्फ्राटेल को खरीदने के लिए 60 दिनों में 3,600 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान करने की पेशकश की है।

सूत्रों के अनुसार, वर्दे पार्टनर्स और यूवीएआरसीएल ने भी इन तीनों कंपनियों के लिए अपनी बोली जमा कराई है लेकिन उन्होंने अग्रिम भुगतान के लिए कोई वादा नहीं किया है। उन्होंने स्पेक्ट्रम सहित अन्य परिसंपत्तियों को भुनाने से प्राप्त रकम लेनदारों को देने की पेशकश की है।

हाल में 29 नवंबर को हुई सचिवों की समिति की बैठक में एसबीआई कैप ने बोलियों का अध्ययन करने के लिए समय मांगा था। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल एक ऐसे खरीदार की तलाश कर रहा है जो ताकि 32,000 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान के लिए रकम जुटाई जा सके जो केवल एक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर लेनदारों का बकाया है। सूत्रों का कहना है कि प्राप्त बोलियो के आधार पर बैंकों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रिलायंस जियो केवल रिलायंस इन्फ्राटेल के लिए बोली लगा रही है ओर यह पेशकश उसकी कारोबारी योजना के अनुकूल है। पिछले साल जियो ने 43,000 रिलायंस इन्फ्रा टावर परिसंपत्ति की खरीदारी के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा वह अपनी फाइबर टु होम परियोजना को चालू करने के लिए 1,78,000 किलोमीटर फाइबर का भी इस्तेमाल कर रही थी। उस समय रिलायंस ने 25,000 करोड़ रुपये की पेशकश की थी जिसमें स्पेक्ट्रम का उपयोग भी शामिल था। लेकिन दूरसंचार विभाग के दबाव के कारण वह सौदा नहीं हो सका। दूरसंचार विभाग का कहना था कि पिछले बकाये के भुगतान के लिए जियो अथवा रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्रवर्तक वादा करे। लेकिन जियो ने वादा करने से इनकार कर दिया। बाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चली गई।

हालांकि सूत्रों ने कहा कि जियो ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जटिलताओं से बचने के लिए स्पेक्ट्रम के लिए बोली न लगाने का निर्णय लिया है।

क्राफ्ट बियर श्रेणी में उतरी यूनाइटेड ब्रुअरीज

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 4 दिसंबर

- कंपनी ने उतारी 'किंगफिशर अल्ट्रा विटबियर'
- भारत में क्राफ्ट बियर का बाजार छोटा है लेकिन स्पेशिएलिटी बियर का तेजी से बढ़ रहा बाजार

यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (यूबीएल) ने अपने नए क्राफ्ट बियर ब्रांड 'किंगफिशर अल्ट्रा विटबियर' को बाजार में उतारते हुए स्पेशिएलिटी बियर श्रेणी में दस्तक दी है। इस बियर में अल्कोहल की मात्रा 5 फीसदी से कम होगी और यह कर्नाटक एवं गोवा में उपलब्ध रहेगा। कंपनी जल्द ही उसे महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में उतारने की तैयारी कर रही है।

यूबीएल के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी ने कहा, 'हालांकि क्राफ्ट बियर के लिए बाजार का आकार सामान्य बियर के मुकाबले काफी छोटा है लेकिन यह तेजी से उभरने वाली श्रेणी है। इस लॉन्च के साथ यूबीएल ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।' 'किंगफिशर अल्ट्रा विटबियर' को बाजार में उतारते हुए कंपनी ने स्पेशिएलिटी बियर श्रेणी में कदम रखा है और 'अल्ट्रा' ब्रांड के तहत अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। बाजार के आकलन के अनुसार, भारत में कुल बियर बाजार के मुकाबले क्राफ्ट बियर के बाजार का आकार 10 फीसदी से भी कम है। करीब 85 फीसदी बाजार पर स्ट्रॉन्ग बियर का वर्चस्व कायम है। हालांकि क्राफ्ट बियर का चलन तेजी से बढ़ रहा है और पिछले एक दशक के दौरान देश में करीब 170 सूक्ष्म ब्रुअरीज स्थापित हुई हैं। यूबीएल के अलावा दो अन्य बियर कंपनियां एनहॉजर-बुश इनबेव और कार्ल्सबर्ग 90 फीसदी से अधिक भारतीय बियर बाजार पर काबिज हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक लोगों द्वारा प्रीमियम ब्रांड को पसंद किए जाने के कारण आगामी तिमाहियों में स्पेशिएलिटी बियर की मांग बढ़ सकती है।

बीएस बातचीत

'अगले 5 साल में दिखेंगे स्टार्टअप आईपीओ'

प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल ने इंडिया हाल में 55 करोड़ डॉलर पर अपने छठे फंड को बंद किया है। वेंचर कैपिटल फर्म ने अब तक 120 से अधिक कंपनियों में निवेश किया है और उनमें से 44 कंपनियों का मूल्यांकन अब 10 करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है। फ्लिपकार्ट और स्विगी में उसके शुरुआती निवेश पर काफी लाभांश मिला। एक्सेल इंडिया के सह-संस्थापक एवं पार्टनर **सुब्रत मित्रा** से **युवराज मलिक** की बातचीत के मुख्य अंश:

पिछले 11 वर्षों के दौरान स्टार्टअप क्षेत्र में 1 अरब डॉलर का निवेश करने के बाद एक्सेल इंडिया अब किस ओर ध्यान केंद्रित कर रही है?

हम शुरू में उन प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते थे जो बड़ी समस्याओं का समाधान करती हैं। हम उने संस्थापकों को सहारा देना चाहते हैं जो अपने कारोबार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले ही दिन से सबकुछ पता होता है बल्कि हम उन्हें तेजी से सीखने में मदद कर सकते हैं। जहां तक क्षेत्रों का सवाल है तो हमारी नजर पांच प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी संपन्न कंपनियों पर है जिसमें उपभोक्ता, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और बिजनेस टु बिजनेस (बी2बी) शामिल हैं।

हाल में आपने सोशल ई-कॉमर्स फर्म सिमसिम में निवेश किया और बाउंस में बड़े दौर के निवेश का नेतृत्व किया। क्या आप नए क्षेत्रों में प्रयोग कर रहे हैं?

वाणिज्यिक सर्वव्यापक है। अब सवाल यह है कि आप कितनी तेजी से उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का ही उदाहरण लीजिए। इस कंपनी ने महज शीर्ष 1 करोड़ (उपयोगकर्ताओं) पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरुआत की थी जो बढ़कर 5 करोड़ हो गया और आज वह करीब 9 करोड़ खरीदारों को अपनी सेवाएं दे रही है। अब अगले 10 करोड़ उपयोगकर्ता ऑनलाइन खरीदारी के लिए तैयार हैं। इन नए उपयोगकर्ताओं के लिए तमाम विशिष्ट समाधानों पर गौर किया जा सकता है। बाउंस के जरिये हमने मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश किया है। ऐसे लाखों उपयोगकर्ता हैं जिन्हें दैनिक आवाजाही की जरूरत है। हम समझते हैं कि इस समस्या के समाधान में काफी संभावनाएं हैं।

वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट सौदे के बाद और हाल में द्वितीयक बिक्री में तेजी आने से ऐसा लगता है कि भारतीय वेंचर कैपिटल उद्योग का चक्र पूरा हो गया है। अगले चक्र के बारे में आप क्या कहेंगे?

इंटरनेट पर 50 करोड़ लोगों के होने के साथ ही हम निश्चित तौर पर दूसरे चक्र में हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। करीब 40 करोड़ लोग रोजाना व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं जबकि 30 से 40 करोड़ लोग रोजाना यूट्यूब को ऐक्सेस करते हैं। जब वही लोग अपने दफ्तर में काम करते हैं तो वे यूट्यूब और व्हाट्सऐप जैसे आसान टूल्स चाहते हैं। मोगलिक्स अथवा ब्लैकबक जैसी हमारी कुछ बी2बी कंपनियों ने कागज-कलम वाली व्यवस्था के बदले एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ कामकाज को आसान बनाया है।

क्या एक निवेशक के तौर पर फ्लिपकार्ट जैसी उथल-पुथल मचाने वाली अगली कंपनी तलाशना आपके के लिए आसान नहीं रह गया है?

जहां तक बी2बी क्षेत्र का सवाल है तो कंपनियां अभी भी शुरुआती चरण में हैं लेकिन उपभोक्ता क्षेत्र अब काफी परिपक्व हो चुका है। उपभोक्ता क्षेत्र में लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। नए उद्यमी सोच रहे हैं कि वे व्हाट्सऐप जैसे आसान टूल्स के साथ आ सकते हैं।

तकनीकी स्टार्टअप में कुछ ही लोगों की अधिक दिलचस्पी बरकरार है, लेकिन वे चाहते हैं कि वे अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के साथ पूंजी बाजार में उतरें। इसमें कितना समय लगेगा?

अगले पांच वर्षों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। निवेशकों को सबसे पहले इस तथ्य को समझना होगा कि वे इस श्रेणी में निवेश करना चाहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर निवेशक आज मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को तलाश रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की कंपनियां तेजी से विकास कर रही हो। वृद्धि और मुनाफा के टिकाऊ होने पर उन्हें खुशी होती है। यही बदलना होगा।

आगाज पर 54 फीसदी चढ़ा सीएसबी बैंक का शेयर

बहुलांश हिस्सेदार फेयरफैक्स ने अपने निवेश में 2.2 गुने की बढ़ोतरी दर्ज की

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 4 दिसंबर

सीएसबी बैंक का शेयर बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ और 54 फीसदी चढ़ गया। यह शेयर 54 फीसदी की उछाल के साथ 300.4 रुपये पर बंद हुआ जबकि आईपीओ कीमत 195 रुपये थी। बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की मिली बड़ी कामयाबी के बाद शानदार सूचीबद्धता देखने को मिली, जिसे कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स की फेयरफैक्स का समर्थन हासिल है। लेनदार के 410 करोड़ रुपये के आईपीओ को 87 गुना आवेदन मिले थे।

इस आईपीओ में मोटे तौर पर मौजूदा निवेशकों मसलन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने शेयर बेचे।

ये संस्थान हालांकि आईपीओ निवेशकों मिले इतने ज्यादा फायदे से शायद निराश होंगे, लेकिन फेयरफैक्स के निवेश की कीमत दो साल से भी कम अवधि में 2.2 गुना बढ़ गई।

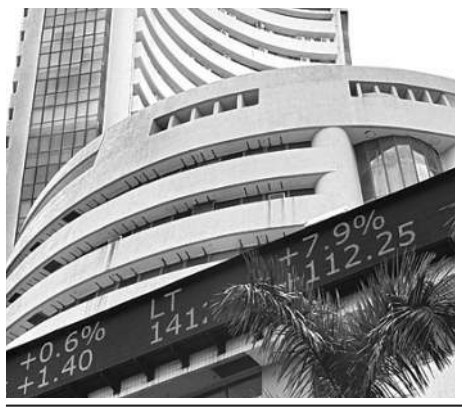

- सीएसबी बैंक का शेयर 54 फीसदी की उछाल के साथ 300.4 रुपये पर बंद हुआ जबकि आईपीओ कीमत 195 रुपये थी

कनाडा की फर्म ने केरल के बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी फरवरी 2018 में 1,200 करोड़ रुपये में खरीदी थी। मौजूदा कीमत पर उनकी हिस्सेदारी की कीमत 2,654 करोड़ रुपये बैठती है।

फेयरफैक्स हालांकि अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 51 फीसदी से धीरे-धीरे घटाकर 15 फीसदी पर लाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेश फर्म को ऐसा करने के लिए कुछ समय दिया है। सीएसबी बैंक का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 5,205 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जबकि आईपीओ कीमत पर यह मूल्यांकन 3,382 करोड़ रुपये रहा था।

सीएसबी बैंक का बाजार मूल्यांकन दक्षिण भारत के अन्य बैंकों मसलन लक्ष्मी विलास बैंक (एमकैप-690 करोड़ रुपये), धनलक्ष्मी बैंक (380 करोड़ रुपये) और साउथ इंडियन बैंक (1,991 करोड़ रुपये) से काफी ज्यादा है।

आईपीओ कीमत पर सीएसबी बैंक का मूल्यांकन उसकी बुक वैल्यू के करीब 2.4 गुने पर है। उसके समकक्ष ज्यादातर बैंक जैसे आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और डीसीबी बैंक के शेयर दो गुने से नीचे पीई पर कारोबार कर रहे हैं।

विगत में कैथलिक सीरियन बैंक के नाम से मशहूर सीएसबी बैंक के शेयर में मिला सूचीबद्धता का फायदा किसी बैंकिंग शेयर में 13 साल का सबसे अच्छा फायदा है। साल 2006 में डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक (अब डीसीबी बैंक) का शेयर 80 फीसदी से ज्यादा चढ़ा था। विश्लेषकों ने कहा कि सीएसबी बैंक के मजबूत नेटवर्क और दक्षिण भारत में ब्रांड की मौजूदगी को देखकर निवेशक आकर्षित हुए।

रिलायंस सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है, अच्छा खासा पूंजी आधार, स्थापित एसएमई बिजनेस मॉडल, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो और जोखिम प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था आदि सीएसबी बैंक की ताकत है।

प्रबंध निदेशक का कार्यकाल बढ़ा

सीएसबी बैंक ने मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सी वीआर राजेंद्रन का कार्यकाल तीन साल बढ़ा दिया है। बैंक को राजेंद्रन के सेवा विस्तार की अनुमति आरबीआई से मिल गई है। राजेंद्रन का मौजूदा गकार्यकाल 9 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रहा था, जिसे अब बढ़ाककर 8 दिसंबर 2022 कर दिया गया है।

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के आईपीओ को 170 गुना आवेदन

बीएस संवाददाता
मुंबई, 4 दिसंबर

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को पेशकश के मुकाबले 170 गुना से ज्यादा आवेदन मिले। संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 114 गुना आवेदन मिले, वहीं धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई) की श्रेणी में 486 गुना और खुदरा श्रेणी में करीब 50 गुना आवेदन मिले।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि आईआरसीटीसी और सीएसबी बैंक की सूचीबद्धता में मिले शानदार फायदे से उत्साहित निवेशक उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक में उच्च बढ़त की संभावना से उसकी पेशकश की ओर आकर्षित हुए।

442 करोड़ रुपये के आईपीओ को करीब 76,000 करोड़ रुपये की बोली मिली। उज्जीवन एसएफबी के इश्यू का कुल आकार करीब 750 करोड़ रुपये का है, हालांकि उसने करीब 300 करोड़ रुपये के शेयरों का आवंटन आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों को किया है।

उज्जीवन एसएफबी इस आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पूंजी आधार बढ़ाने में करेगा। हालांकि सूचीबद्धता की प्राथमिक वजह स्मॉल फाइनैंस बैंक पर आरबीआई के दिशानिर्देश का अनुपालन है।

उज्जीवन एसएफबी, उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है। केंद्रीय बैंक ने सभी स्मॉल फाइनैंस बैंक को एकल इकाई के तौर पर कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर सूचीबद्ध होना अनिवार्य किया है।

इस आईपीओ के बाद उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी बैंक में 100 फीसदी घटकर 84 फीसदी रह जाएगी।

आईपीओ में आवेदन

श्रेणी	आवेदन (गुना)
क्यूआईबी	114
एचएनआई	486
खुदरा	50
कुल	170

उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज का शेयर बुधवार को 4 फीसदी उछला।

निवेश बैंकरों के मुताबिक, काफी ज्यादा आवेदन मिलने से यह आईपीओ सबसे ज्यादा आवेदन पाने वाली कंपनियों से एक बन गई। बैंकरों ने कहा, भारी मांग को देखते हुए 36 खुदरा निवेशकों में से सिर्फ एक को शेयर आवंटित होगा।

इस इश्यू का कीमत दायरा 36 से 37 रुपये था। आईपीओ कीमत पर उज्जीवन एसएफबी का मूल्यांकन करीब 6,300 करोड़ रुपये होगा। इस इश्यू की कीमत 2020-21 के अनुमानित बुक वैल्यू का करीब दोगुना है। ज्यादातर विश्लेषकों ने उज्जीवन एसएफबी के आईपीओ के लिए आवेदन की सिफारिश निवेशकों से की थी।

एफऐंडओ में फर्जीवाड़े पर आयकर विभाग सख्त

पृष्ठ-1 का शेष

नियामक द्वारा अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के दौरान बीएसई पर न के बराबर खरीद-बिक्री वाले स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई थी। इस जांच में सेबी को बीएसई के स्टॉक ऑप्शन खंड में बड़े पैमाने पर सौदों की खरीद-बिक्री का पता चला था।नियामक ने पाया कि कुछ इकाइयां बार-बार स्टॉक आप्शन की खरीद-बिक्री कर रही थीं। एक बार किसी स्टॉक ऑप्शन को खरीदने के बाद उसे बेच दिया जाता था और फिर थोड़े ही समय अंतराल में उतनी ही मात्रा में उस स्टॉक ऑप्शन को संबंधित इकाई द्वारा खरीद लिया जाता था लेकिन दोनों की कीमतों में काफी अंतर होता था। इस प्रकार ये इकाइयां अनुबंधों में कृत्रिम वॉल्यूम पैदा करती थीं, जो उचित व्यापार व्यवहार नियमों का उल्लंघन है।यह आदेश सेबी की अप्रैल 2008 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें नियामक ने फर्जी तरीके से इस तरह के स्टॉक ऑप्शन खंड में कारोबार करने वाली 14,720 इकाइयों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्णय किया था।

बाजार नियामक अब तक ऐसी 60 से 70 इकाइयों के खिलाफ आदेश दे चुका है।इसके तरीके की जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर प्रतिभूति लेनदेन कर चुकाया जाता था लेकिन 12 महीने से अधिक समय तक निवेश बनाए रखने पर दीर्घावधि पूंजी लाभ कर नहीं लगता है। हालांकि सेबी और आयकर विभाग ने पाया कि न बिकने वाले शेयरों की कीमतों में हेरफेर कर इस प्रावधान का अक्सर दुरुपयोग किया जाता था। ऑपरेटर लाभार्थियों को ऐसी सूचीबद्ध फर्मों में निवेश की सलाह देते थे, और मामूली भाव पर तरजीही शेयर आवंटित किया जाता था। इन शेयरों की लॉक-इन अवधि एक साल की होती है। इस तरह से ये ऑपरेटर इन शेयरों की कीमतों में हेरफेर करते थे। ये संबंधित इकाइयों को दीर्घावधि पूंजी लाभ के लिए अंतिम ट्रेडेड भाव मुहैया कराते थे और शेयर की खरीद ऊंची कीमत पर दिखाते थे।

यूटीआई एएमसी आईपीओ में 8.25 फीसदी हिस्सा बेचेगा एसबीआई

बीएस संवाददाता
मुंबई, 4 दिसंबर

भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में वह 8.25 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा। अभी एसबीआई के पास यूटीआई म्युचुअल फंड की 18.25 फीसदी हिस्सेदारी है। तीन अन्य सरकारी उपक्रमों एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नैशनल बैंक के पास 18.25-18.25 फीसदी हिस्सेदारी है, वही टी रो प्राइस की हिस्सेदारी 26 फीसदी है।

सूत्रों ने कहा कि एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी भी यूटीआई एमएमसी के आईपीओ में 8.25-8.25 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकते हैं।

आईपीओ में कुल मिलाकर 33 फीसदी हिस्सेदारी बिक सकती है। अगर इस आईपीओ में नए शेयर होंगे तो ज्यादा हिस्सा बिक सकता है।

एसबीआई की तरफ से प्रस्तावित 8.25 फीसदी विनिवेश बाजार नियामक सेबी के क्रॉस शेयरहोल्डिंग नियमों के अनुपालन के लिए जरूरी वास्तविक मात्रा है। सेबी के नियम में किसी एक इकाई को एक फंड हाउस में 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा रखने की अनुमति नहीं है। अभी एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूटीआई एएमसी में अपनी हिस्सेदारी के साथ अलग-अलग फंड हाउस का परिचालन भी करते हैं।

एसबीआई ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में कहा, सेबी के नियम के प्रावधानों के मुताबिक बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति को आज हुई बैठक में यूटीआई एएमसी में एसबीआई की 8.25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी।

देश का सातवां सबसे बड़ा म्युचुअल फंड बाजार नियामक सेबी के पास दिसंबर के आखिर में पेशकश दस्तावेज जमा करा सकता है।

यूटीआई एएमसी इस आईपीओ में 10,000 करोड़ रुपये से लेकर 13,000 करोड़ रुपये का मूल्यांकन चाह सकती है। इस साल परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनियों के शेयरों में तेजी से इस इश्यू को सहारा मिल सकता है। एचडीएफसी एमएफ और निप्पॉन इंडिया एमएफ (विगत में रिलायंस एमएफ) का शेयर इस साल अब तक क्रमश: 122 फीसदी और 120 फीसदी चढ़ा है।

सितंबर तिमाही के आखिर में यूटीआई एमएफ के पास 1.54 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां थीं, वहीं एचडीएफसी एमएफ और निप्पॉन एमएफ क्रमश: 3.8 लाख करोड़ रुपये व 2 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है।

अंकेक्षकों के विनियमन में नहीं पड़ना चाहता सेबी

सेबी प्रमुख ने कहा कि ऑडिट फर्मों के खिलाफ कार्रवाई में वह अपने अधिकारों के दायरे में है

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 4 दिसंबर

बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने बुधवार को कहा कि अंकेक्षकों के विनियमन की लड़ाई में वह नहीं पड़ना चाहता। त्यागी ने कहा कि सेबी किसी इकाई को सूचीबद्ध फर्मों के अंकेक्षण की अनुमति नहीं दे सकता, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता हो।

ऑडिट फर्मों को सुरक्षा प्रहरी बताते हुए सेबी प्रमुख ने कहा कि अगर अंकेक्षित सूचीबद्ध फर्मों में खामियां पाई जाती है तो अंकेक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के सम्मेलन को संबोधित करते हुए त्यागी ने कहा, हमारा रुख साफ है, अगर वे सूचीबद्ध फर्मों का अंकेक्षण कर रहे हैं और इसके आधार पर निवेशक फैसले ले रहा है और अगर हमें पता चलता है कि काम सही तरीके से नहीं किया गया तो निवेशकों के हित में ऑडिट फर्मों को कुछ समय तक सूचीबद्ध फर्मों का अंकेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें यह देखने का अधिकार है कि वे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं और अगर वे चुनौती देना चाहते हैं तो हम भी चुनौती देंगे।

यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिभूति अपील पंचाट ने हाल में पाया है कि सेबी के पास सूचीबद्ध कंपनियों के अंकेक्षण से अंकेक्षकों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात सत्यम घोटाले में प्राइस वाटरहाउसकूपर्स की अपील की सुनवाई में सैट ने कही थी। सेबी ने सैट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और इस पर स्टे हासिल करने में कामयाब रहा।

त्यागी ने कहा कि सेबी की प्राथमिक जिम्मेदारी निवेशकों की सुरक्षा है और खामियों की स्थिति में ऑडिट फर्मों को जिम्मेदार ठहरा सकता है। उन्होंने कहा, यह कहना कि हमें मामले को पंजीकरण वाले प्राधिकरण के पास संदर्भित कर देना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है।

इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से अंकेक्षकों से इस्तीफे के मामले में भी नियमों में सख्ती की है। बाजार नियामक ने कहा है कि अंकेक्षकों को उस तिमाही के लिए सीमित या पूरी अंकेक्षण रिपोर्ट देनी होगी, जब वह इस्तीफा दे रहा हो।

आईपीओ बाजार के बारे में सेबी प्रमुख ने कहा कि यहां सुधार देखने को मिला है और करीब 15,000 करोड़ रुपये के एक दर्जन आईपीओ आने वाले हैं। त्यागी ने कहा कि आईएलऐंडएफएस संकट के बाद बाजार में आए उतारचढ़ाव ने आईपीओ के सेंटिमेंट पर चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि आईपीओ बाजार के लिए कोई नियामकीय अवरोध नहीं है। हम पहले ही उन कंपनियों के लिए शुल्क घटा चुके हैं अगर मंजूरी के बाद समयसीमा समाप्त हो जाती है और कंपनियां आईपीओ के लिए दोबारा आवेदन करती हैं।

कार्वी के गिरवी शेयरों के स्वामित्व पर सेबी व लेनदारों के बीच विवाद पर त्यागी ने कहा कि नियामक सैट के आदेश का पालन करेगा। उन्होंने कहा, अगर और ब्रोकर ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए तो सेबी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

सेबी प्रमुख की बेबाक राय

- त्यागी ने कहा कि सेबी किसी इकाई को सूचीबद्ध फर्मों के अंकेक्षण की अनुमति नहीं दे सकता, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता हो
- सेबी प्रमुख ने कहा कि अगर अंकेक्षित सूचीबद्ध फर्मों में खामियां पाई जाती है तो अंकेक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए
- आईपीओ बाजार के बारे में सेबी प्रमुख ने कहा कि यहां सुधार देखने को मिला है और करीब 15,000 करोड़ रुपये के एक दर्जन आईपीओ आने वाले हैं

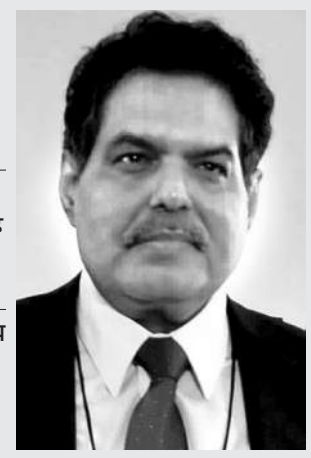

2022 तक ई-कॉमर्स एफएमसीजी बिक्री 5 फीसदी पर पहुंचेगी : नीलसन

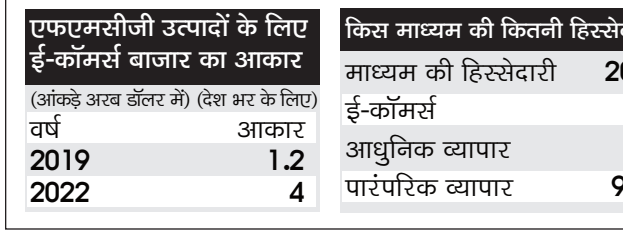

कुल ब्रांडेड एफएमसीजी की बिक्री में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी (आंकड़े फीसदी में)

वर्ष	हिस्सेदारी
2016	0.5
2019	2
2022	5

मार्केट रिसर्च एजेंसी नीलसन ने बुधवार को कहा कि ई-कॉमर्स के जरिये एफएमसीजी की बिक्री साल 2022 तक 5 फीसदी पर पहुंच जाएगी, जो अभी दो फीसदी है क्योंकि उपभोक्ता ज्यादातर खरीद ऑनलाइन करने लगे हैं। नीलसन के अध्यक्ष (दक्षिण एशिया) प्रसून बसु ने कहा, इससे भारत में एफएमसीजी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स का बाजार मौजूदा 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर 4 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा, जिसकी अगुआई मेट्रो बाजार करेंगे। उन्होंने कहा, एफएमसीजी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स के प्रसार के लिहाज से मौजूदा 2 फीसदी पर भारत पहले से ही कनाडा, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे बाजारों के बराबर है। अमेरिका और ब्रिटेन में इसका प्रसार क्रमशः 5.5 फीसदी और 6 फीसदी है। फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया में एफएमसीजी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स का प्रसार 7 फीसदी, 17 फीसदी और 20 फीसदी है। बसु ने कहा, अगले चार साल में भारत में ई-कॉमर्स चैनल की सालाना चक्रवृद्धि रफ्तार 44 फीसदी होगी जबकि पारंपरिक कारोबार की 8 फीसदी और आधुनिक कारोबार की रफ्तार करीब 20 फीसदी होगी।

विवेट सुजन पिंटो

एफएमसीजी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स बाजार का आकार
(आंकड़े अरब डॉलर में) (देश भर के लिए)

वर्ष	आकार
2019	1.2
2022	4

किस माध्यम की कितनी हिस्सेदारी (आंकड़े फीसदी में)

माध्यम की हिस्सेदारी	2016	2019	2022
ई-कॉमर्स	0.5	2	5
आधुनिक व्यापार	8	10	11
पारंपरिक व्यापार	91.5	88	84

आईसीआईसीआई बैंक के नजरिये को बाजार ने सराहा

डिजिटल क्षमता कम लागत में बैंक की बढ़त में करेगा सुधार

श्रीपाद ऑटे
मुंबई, 4 दिसंबर

आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बुधवार को 4 फीसदी बढ़त के साथ 529.35 रुपये पर बंद हुआ, लेकिन इससे पहले यह शेयर 531.35 रुपये के सर्वोच्च स्तर को छू गया। बैंक की तरफ से विश्लेषकों के सामने अपना कारोबारी नजरिया रखने के एक दिन बाद शेयर में बढ़त देखने को मिली है।

विश्लेषकों से बातचीत में बैंक ने मुख्य रूप से अपनी डिजिटल और तकनीकी पहल के बारे में बताया, जिससे कारोबार के सभी क्षेत्रों को तेज गति से बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। 'वन बैंक, वन आरओई' अपना परिचालन लाभ बढ़ाने के लिए जोखिम को समायोजित करने के अलावा बैंक पूरी व्यवस्था में उपलब्ध मौके पर ध्यान केंद्रित करेगा। आरओई का मतलब इक्विटी पर रिटर्न है और यह लाभप्रदता का संकेतक है। विश्लेषकों का मानना है कि इन कोशिशों से आय में मजबूती आ सकती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि दो साल में बैंक का आरओई 15 फीसदी से ज्यादा रहेगा, जो वित्त वर्ष 2020 में 10 फीसदी से नीचे रहने का अनुमान है।

उदाहरण के लिए गुणवत्ता वाले नए कारोबार हासिल करने में तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ परिचालन लागत घटाने में मदद मिलेगी बल्कि क्रेडिट की लागत भी कम होगी (औसत लोनबुक के प्रतिशत के तौर पर फंसे कर्ज के लिए प्रावधान)। डिजिटलीकरण व तकनीक हमेशा से ही बैंक के केंद्र में रही है, लेकिन पिछले एक साल से बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रबंधन के मसले से जूझ रहा था। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, चूंकि परिसंपत्ति गुणवत्ता का मसला सुलझ गया है, लिहाजा आईसीआईसीआई बैंक ठीक-ठाक और स्थायी बढ़त हासिल करने की स्थिति में नजर आ रहा है, जिसकी अगुआई तकनीक व में लगातार हो रहे निवेश और डिजिटल पेशकश में और विस्तार करेगा।

कंपनियों को कर्ज देने के मामले में ए रेटिंग वाली कंपनियों पर ध्यान और कीमत के बजाय पूंजी की वापसी पर ध्यान से बैंक के थोक कारोबार का प्रदर्शन और सुधर सकता है।

विश्लेषकों ने कहा, कुल मिलाकर बैंक की कोशिश सही दिशा में नजर आ रही है। पिछले एक महीने में निफ्टी बैंक में 5.3 फीसदी की बढ़त के मुकाबले इस बैंक का शेयर 12.5 फीसदी उछलने के बावजूद ज्यादातर विश्लेषक अब इस शेयर में दोबारा रेटिंग की संभावना देख रहे हैं। एडलवाइस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा, हमें लगता है कि इस शेयर में दोबारा रेटिंग की क्षमता है क्योंकि बाजार को आय में स्थिर से भरोसा हासिल हो रहा है।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार के घटनाक्रम के बाद कई विश्लेषकों ने इस शेयर की लक्षित कीमत 19 फीसदी तक बढ़ाकर 567 रुपये कर दी है।

बीएस बातचीत

आसान नकदी के फायदे वित्त वर्ष 2020 के आखिर में नजर आएंगे

ऐक्सिस म्युचुअल फंड के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) **आर. शिवकुमार** ने **हंसिनी कार्तिक** को दिए साक्षात्कार में कहा कि व्यवस्था में नकदी अच्छी खासी सुधरी है पर उपभोग में इजाफे के लिए सरकार की तरफ से कुछ और कदम उठाए जाने की दरकार है। मुख्य अंश...

पिछले एक साल में नकदी में कितना सुधार हुआ है?
पिछले साल और नोटबंदी के बाद के करीब दो साल में हमने जिस तरह का नकदी संकट देखा था, उसमें अब बदलाव आया है। नीतिगत दरों में भी काफी कटौती हुई है। अंतर-बैंक दरें भारतीय रिजर्व बैंक के रीपो दर से नीचे है। व्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी है और आरबीआई ने अपना रुख बदलकर उदार कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि चीजें और खराब होंगी। लेकिन बेहतरी में थोड़ा वक्त लगने वाला है। 2019-20 के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में हम वास्तव में आसान नकदी के फायदे अर्थव्यवस्था में दिखने लगेंगे।

नकदी उचित स्तर पर है और सकल घरेलू उत्पाद 26 तिमाही के निचले स्तर पर है। ऐसे में बाजार ब्याज दरों में कितनी कटौती मानकर चल रहा है?
बाजार ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती का अनुमान लगा रहा है। लेकिन दिलचस्प रूप से ये प्रवृत्तियां अलग-अलग हैं - एक ओर जहां प्रतिफल के ग्राफ का निचला सिरा इस तरह व्यवहार कर रहा है कि वह दरों में कटौती मानकर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस ग्राफ का ऊपरी सिरा अलग व्यवहार कर रहा है। आरबीआई उदार रुख का वादा कर रहा है - यहां दरों में कटौती या यथास्थिति के बीच चयन होना है। व्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये की नकदी का मतलब यह है कि प्रतिफल के ग्राफ के निचले सिरे को फायदा होगा। हालांकि राजकोषीय घाटे पर चिंता का मतलब यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल नहीं घटेगा।

ब्याज दरों में और कटौती के मुकाबले आप कटौती का फायदा आगे देने की जरूरत पर मुखर रहे हैं?
यह सही है। आरबीआई ने हालांकि ब्याज दरें घटाई है, लेकिन बैंकों की तरफ से ब्याज में इस हिसाब से कमी नहीं की गई है। बैंक जमा दरें और उधारी दरें उच्चस्तर पर बनी हुई है। दिसंबर 2018 से आज तक बैंकों की उधारी दर उसी स्तर पर है या इससे थोड़ा ऊपर ही है। आरबीआई ने हालांकि कहा है कि नए कर्ज पर भारांकित औसत उधारी दर कम हुई है, लेकिम हमें नहीं पता कि यह कितना कम हुआ है। बैंकिंग व्यवस्था की वित्तीय स्थिति भी सख्त है। हमें और सरकारी कदमों की दरकार है।

भारत बॉन्ड ईटीएफ को कैबिनेट की मंजूरी

अनूप रॉय और समी मोडक
मुंबई, 4 दिसंबर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के पहले बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 'भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)' नाम से एक साझा निवेश कोष शुरू करने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसकी खरीद और बिक्री किसी भी सूचीबद्ध प्रतिभूति की तरह किसी भी एक्सचेंज पर की जा सकेगी।

यह ईटीएफ सरकार से जुड़ी कंपनियों द्वारा जारी एएए रेटेड पेपर्स से बना होगा और इसकी दो परिपक्वता 3 साल व 10 साल होगी। सूत्रों ने कहा कि यह पेशकश जनवरी के पहले सप्ताह में की जाएगी। बॉन्ड ईटीएफ के पहले हिस्से की पेशकश एडलवाइज असेट मैनेजमेंट करेगी, लेकिन इसके अन्य हिस्से भी आएंगे, जिनके लिए अन्य संपत्ति प्रबंधकों की नियुक्ति की जा सकती है। एके कैपिटल सर्विसेज डेट ईटीएफ के लिए सरकार की पूर्ण सलाहकार है।

इससे खुदरा ग्राहक बॉन्ड बाजार में आकर्षित होंगे, जो लंबे समय से सरकार और नियामक का सपना था और इससे दीर्घावधि के हिसाब से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में मजबूती आएगी। सरकार ने एक बयान में कहा है कि निवेशक ईटीएफ की यूनिट 1000 रुपये तक में खरीद सकेंगे।

> 'विस्तृत दायरे वाले इस ईटीएफ के सृजन तथा इसकी शुरुआत से हमें उम्मीद है कि निवेशकों का आधार बड़ा होगा। यह खुदरा निवेशकों को छोटी मात्रा में बॉन्ड में निवेश करने की सहूलियत देगा। इस कोष के शुरू होने पर सरकारी कंपनियों तथा अन्य सरकारी संगठनों के लिए अतिरिक्त धन जुटाने में मदद मिलेगी'

डेट मार्केट के विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि बॉन्ड ईटीएफ से निश्चित रूप से खुदरा निवेशकों को मदद मिलेगी और वे डेट मार्केट में दिलचस्पी ले सकेंगे और इसमें न्यूनतम जोखिम से बगैर जोखिम लिए मुनाफे का अनुमान लगा सकेंगे।

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में नियत आय के प्रमुख बद्रीश कुलहल्ली ने कहा, 'खुदरा निवेशक उचित कीमत, खराब कीमत, उपार्जित ब्याज आदि जैसे शब्दजालों में उलझ जाते हैं। निवेशकों के लिए ईटीएफ म्युचुअल फंड जैसा है, जिसका एक साफ सुथरा एनएवी ढांचा है और एक्सचेंज में इसका कारोबार हो सकता है। यह कुछ ऐसा है, जिसे कोई व्यक्ति समझ सकता है।' कुलहल्ली ने कहा कि खुदरा निवेशकों के लिए निवेश आसान करने वाला कोई भी फैसला स्वागत योग्य कदम है।

बयान में कहा गया है कि इस ईटीएफ में सरकारी कंपनियों या किसी सरकारी संगठन द्वारा जारी किए गए बॉन्ड होंगे और इनका शेयर बाजारों में कारोबार किया जा सकेगा, जिसकी वजह से ये सुरक्षित होंगे। इसकी एक यूनिट का अंकित मूल्य बहुत कम (1000 रुपये) रखा जाएगा ताकि आसान और कम पैसे के बॉन्ड बाजार उपलब्ध हो सके। इससे खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जो इस समय नकदी कम होने और तमाम बाधाओं की वजह से बॉन्ड बाजार में नहीं आते। बयान में कहा गया है कि यह निवेश बॉन्डों की तुलना में कर प्रभावी होगा। इन पर मामूली दर से कर लगेगा, जबकि बॉन्ड ईटीएफ पर इंडेक्सेशन के लाभ के साथ कर लगता है।

इस उत्पाद की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ होगा, जिससे सरकारी कंपनियों व अन्य सरकारी संगठनों को अतिरिक्त धन मिल सकेगा।

एडलवाइज एएमसी की सीईओ राधिका गुप्ता ने कहा, 'यह पूरी ततरह से उच्च गुणवत्ता के सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड होंगे। अब उधारी लेने वालों के पास समयावधि की लंबी सीमा मिलेगी और निवेशकों के पास डेट उत्पादों की पूरी रेंज होगी।'

एके कैपिटल के एसोसिएट डायरेक्टर पंकज अग्रवाल ने कहा, 'पारदर्शिता, नकदी और निवेशकों की व्यापक हिस्सेदारी बॉन्ड ईटीएफ का मुख्य सिद्धांत है। यह जारीकर्ता व निवेशकों दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। भारत बॉन्ड ईटीएफ भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में व्यापक बदलाव लाएगा।'

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसयू), केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां (सीपीएसई) केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (सीपीएफआई) और अन्य सरकारी संगठनों के लिए इस ईटीएफ के माध्यम से धन जुटाना आसान होगा और इससे बेहतर मूल्य की तलाश में मदद मिलेगी। ईटीएफ इन इकाइयों द्वारा जारी बॉन्डों का बॉस्केट होगा।

सरकार ने सरकारी इकाइयों के लिए डेट इश्यूएंस कैलेंडर लाने की योजना बनाई है। इस व्यापक डेट कैलेंडर से सीपीएसई की उधारी की जरूरतों का आकलन हो सकेगा जिसकी तैयारी व मंजूरी हर साल होगी।

जीएसटी मुआवजा भुगतान का राज्यों को दिया भरोसा

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा के भुगतान का भरोसा दिया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए काई समयसीमा नहीं बताई है। राज्यों को अगस्त और सितंबर महीने के जीएसटी मुआवजा का भुगतान किया जाना है। पंजाब, केरल, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रियों ने बुधवार को सीतारमण से मुलाकात कर अगस्त से बकाये चार महीनों के जीएसटी मुआवजा शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। दिल्ली में 17 और 18 दिसंबर को होने जा रही जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में यह मामला सबसे अधिक विवादित हो सकता है।

जीएसटी का हाल

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि सीतारमण ने उन्हें भरोसा दिया कि पैसा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने फंड जारी किए जाने की कोई समयसीमा नहीं दी। अगस्त और सितंबर महीने की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है और अब अक्टूबर तथा नवंबर महीने की क्षतिपूर्ति भी दिसंबर में की जानी है।

अगस्त और सितंबर के लिए राजस्थान का क्षतिपूर्ति बकाया 4,400 करोड़ रुपये, पंजाब का 2,100 करोड़ रुपये, दिल्ली का 2,355 करोड़ रुपये, केरल का 1,600 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल का 1,500 करोड़ रुपये है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वित्त मंत्री ने इसका कोई कारण नहीं बताया कि राज्यों की क्षतिपूर्ति रकम को किस लिए रोक कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को तीन महीनों- अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए दिल्ली को 3,600 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

राज्यों को राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की खातिर जीएसटी के तहत उपकर संग्रह चालू वित्त वर्ष में जरूरत से कम है। इसकी वजह मांग में आई कमी है। कानून के मुताबिक यदि राज्यों के जीएसटी राजस्व में कम से कम 14 फीसदी की वृद्धि नहीं होती है तो केंद्र सरकार उन्हें प्रत्येक दो महीने बाद उसके अंतर का भुगतान करती है।

मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश का केंद्र पर जीएसटी मुआवजा बकाया अगस्त से नवंबर महीने तक का करीब 3,000 करोड़ रुपये है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की वेबसाइट से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश का जीएसटी संग्रह सबसे खराब रहा है और वह वार्षिक लक्ष्य का 30 प्रतिशत ही संग्रह कर सका। केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने करीब 33 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।

केंद्र ने राज्यों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है कि राज्यों के मुआवजा की जरूरतें संग्रह किए गए उपकर से पूरा नहीं किया जा सकेगा और उसने मुआवजा उपकर व जीएसटी दरों की समीक्षा करने के लिए राज्यों से सलाह मांगी है।

सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र इन दायित्वों से बंधा हुआ है कि वह राज्यों के हितों की रक्षा करे। इस साल पहले 6 महीने में जहां केंद्र ने मुआवजा उपकर महज 46,000 करोड़ रुपये एकत्र किया है, वहीं राज्यों को दिया जाने वाला वास्तविक मुआजा 66,000 करोड़ रुपये हो गया है। संग्रह के हिसाब से जहां वाहनों की बिक्री में गिरावट से संग्रह घटा है, वहीं राज्यों के जीएसटी राजस्व में कुल मिलाकर संकट की स्थिति है, जिससे मुआवजा जारी करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

जीएसटी आयुक्तों को भेजे गए पत्र को बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखा है, जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ महीने से जीएसटी और मुआवजा उपकर संग्रह कम होना चिंता का विषय रहा है और मुआवजा उपकर से मुआवजे की जरूरत पूरी हो पाना संभव नहीं लगता।

इसके अलावा राजस्व बढ़ाने के लिए अनुपालन व दरों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। इसमें छूट की श्रेणी में शामिल वस्तुओं की समीक्षा शामिल है। छूट की सूची में आवश्यक जिंस जैसे अनाज, सब्जियां फल आदि शामिल हैं।

नागरिकता संशोधन मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

सूत्रों ने बताया कि 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधन करने वाले इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

विपक्षी दल इस विधेयक को बांटने वाला एवं सांप्रदायिक बता रहे हैं। इसे भाजपा की विचारधारा से जुड़े महत्त्वपूर्ण आयाम का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें शरणार्थी के तौर पर भारत में रहने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से ज्यादातर लोग हिंदू हैं। इसके माध्यम से उन्हें उस स्थिति में संरक्षण प्राप्त होगा जब केंद्र सरकार देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजी की योजना को आगे बढ़ाएगी।

बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार सभी के हितों और भारत के हितों का ध्यान रखेगी। कुछ वर्गों द्वारा इसका विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोग देश के हित में इसका स्वागत करेंगे। समझा जाता है कि सरकार इसे अगले दो दिनों में संसद में पेश करेगी और अगले सप्ताह इसे पारित कराने के लिए आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, 'मुझे लगता है कि विधेयक असंवैधानिक है क्योंकि विधेयक में भारत के मूलभूत विचार का उल्लंघन किया गया है। वो लोग जो यह मानते हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्धारण होना चाहिए। इसी विचार के आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ।' *भाषा*

अन्य अहम फैसले

- **लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी**
- **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी, मिलेंगी बुनियादी जरूरतें व सुरक्षा**
- **भारत निर्वाचन आयोग और मालदीव के चुनाव आयोग के बीच चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी**
- **केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी, इसके तहत संस्कृत के तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा**

गिग वर्कर्स को मिल सकता है बीमा कवर

सोमेश झा
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

देश में पहली बार गिग इकोनॉमी में काम कर रहे कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दिए जाने वाले बीमा लाभ मिल सकते हैं। यह कदम सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2019 का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दे दी। इस संहिता में बागान मजदूरों को भी पहली बार ईएसआईसी के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है।

गिग वर्कर सामान्यतया शेयरिंग इकोनॉमी में काम करने वाले जैसे उबर, ओला के चालक, जोमैटो, स्विगी आदि के डिलिवरी पर्सन के रूप में काम करने वालों को कहा जाता है। इस तरह की नौकरियां टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, जहां कर्मचारी कंपनी से बंधे नहीं होते और वे उतने समय के लिए अपना काम चुन सकते हैं, जितने समय तक काम करना चाहते हैं।

ईएसआई कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां कम से कम 10 कर्मचारी हैं। बहरहाल खतरनाक काम वाले प्रतिष्ठानों में एक कामगार पर भी यह लागू होगा। इसमें यह विकल्प भी दिया गया है कि 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां भी ईएसआई योजना का लाभ अपने कर्मचारियों को दे सकती हैं।

सामाजिक सुरक्षा

नियत अवधि के कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को नियत अवधि कर्मचारी के रूप में भी जाना जाता है, जिनके लिए 5 साल सेवा पूरी करने पर ग्रेचुटी का प्रावधान है। इस प्रस्ताव से सुनिश्चित होगा कि नियत अवधि के कर्मचारियों को वही लाभ मिल सकेगा, जो स्थाई कर्मचारियों को मिलते हैं।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के मुताबिक इस समय 5 साल सेवा पूरी करने के पहले कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होते हैं। कानून में कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, अस्थायी या स्थायी कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, जिन्होंने लगातार 5 साल सेवाएं दी हैं।

सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी बीमा योजना (ईपीएस) और ईएसआई योजना को छोड़कर अन्य उत्पाद चुनने के प्रस्ताव को हटा दिया है। कंपनियों को ईएसआई योजना में कर्मचारियों के वेतन का 4 प्रतिशत अंशदान करना होगा।

मसौदा प्रस्ताव में सरकार ने ईपीएस और एनपीएस में अदला बदली का विकल्प देने का प्रस्ताव किया था। इसमें कर्मचारियों को ईएसआई और अन्य बीमा फर्मों को चुनने का विकल्प भी दिया गया था। इन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया है। उद्योग संगठनों व मजदूर संगठनों दोनों के विरोध के कारण सरकार ने ईपीएस व एनपीएस की अदला बदली का प्रस्ताव वापस लिया है।

नवंबर में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

नवंबर में गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार दो महीनों के संकुचन के बाद सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पटरी पर आ गई है। बुधवार को एक वैश्विक सर्वे रिपोर्ट में यह जानकारी आई है।

निक्केई इंडिया सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) 52.7 पर रहा, जो अक्टूबर के 49.2 और सितंबर के 48.7 से ज्यादा है। अगर पीएमआई 50 अंक से ऊपर हो इससे विस्तार और इससे कम होने पर संकुचन का पता चलता है। अगस्त महीने में वृद्धि 43 महीने के उच्च स्तर 54.7 पर थी।

यह विनिर्माण गतिविधियों की राह पर है, जिसमें नवंबर में बढ़ोतरी हुई थी और यह 51.2 पर था। इसी सर्वे के मुताबिक अक्टूबर में यह 2 साल के निचले स्तर पर था। यह रिपोर्ट इस सप्ताह की शुरुआत में जारी हुई थी।

बहरहाल जहां विनिर्माण फर्मों ने नौकरियों में 20 महीनों में पहली बार कटौती की है, जिससे लागत में तेजी से कमी आ सके, वहीं सेवा प्रदाताओं ने भर्तियां जारी रखी हैं। सर्वे में कहा गया है कि नौकरियों का विस्तार तीन महीने के उच्च स्तर पर रहा।

अक्टूबर की स्थिरता के बाद नए कारोबारी ऑर्डर मिलने की वजह से सेवा क्षेत्र का विस्तार 4 महीने के उच्च स्तर पर रहा। जिन कंपनियों ने बेहतर बिक्री की रिपोर्ट दी है, उनके मांग की स्थिति अच्छी थी। नवंबर के आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से नए कारोबार में बढ़ोतरी हुई है और अक्टूबर महीने से निर्यात वृद्धि दर धीरे धीरे बढ़ रही है।

सेवा उद्योग में उपभोक्ता सेवाएं, सूचना एवं संचार और रियल एस्टेट और कारोबारी सेवाओं में पीएमआई द्वारा मॉनिटरिंग वाली 5 श्रेणियों में 3 में तेजी देखी गई है। लेकिन ट्रांसपोर्ट और भंडारण और वित्त एवं बीमा फर्मों के कारोबार में सुस्ती रही।

एनएचएआई आंकड़े जारी करने में दिखा रहा है सुस्ती

अमृता पिल्लई
मुंबई, 4 दिसंबर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी उन सरकारी एजेंसियों में शामिल हो गया है जहां से आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। इस उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क ठेका आवंटन और उसके क्रियान्वयन से जुड़ी सार्वजनिक जानकारियां कम आ रही हैं और अनियमित हो गई हैं।

सड़क कंपनियों को एनएचएआई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मशविरा देने वाली कंपनी के एक कार्यकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'जारी किए जाने वाली जानकारियों में कमी आ रही है। राजमार्गों के आंकड़ों का उस तरह से अद्यतन नहीं हो रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। मासिक स्तर पर जारी किए जाने वाली जानकारियों को तिमाही और तिमाही स्तर पर जारी किए जाने वाली जानकारियों को छमाही स्तर पर दिया जा रहा है।'

उदाहरण के लिए राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट पर एमआईएस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछली मासिक रिपोर्ट सितंबर 2018 की है। पिछले वित्त वर्ष (2017-18) में सभी महीनों की रिपोर्ट अपलोड की जाती थी। एमआईएस रिपोर्ट में ठेका का आवंटन, उसका क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण, ठेके की कार्य प्रगति सहित विभिन्न जानकारियां शामिल होती हैं।

एक अन्य कर्मचारी ने कहा, 'एनएचएआई की नई वेबसाइट शुरू होने के बाद से वे एमआईएस की रिपोर्ट का अद्यतन छह महीने में करते थे बाद में यह भी रुक गया।' उन्होंने माना कि आंकड़ों की उपलब्धता अनियमित हो चुकी है। नया वेबसाइट अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था।

उन्होंने कहा, 'निविदा खंड को उन्हें प्रत्येक निविदा के बाद अद्यतन करना होता है लेकिन ये आंकड़े प्राथमिक हैं और उन्हें एमआईएस रिपोर्ट की तर्ज पर तैयार नहीं किया गया है।' एनएचएआई की मुख्य वेबसाइट से ही विभिन्न निविदाओं के संबंध में जानकारी मिल जाती है। प्राधिकरण भी मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटित बोली शीर्षक से आंकड़े साझा करता है। इस मामले के जानकार कर्मचारियों ने कहा कि ये आंकड़े अनियमित आधार पर बदले जाते हैं और कभी कभी कई महीनों तक इनमें बदलाव नहीं किया जाता है। एनएचएआई के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू और प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नही आया।

आंकड़ों का संकट

- **एनएचएआई भी उन सरकारी एजेंसियों में शामिल हो गया है जहां से आंकड़े नहीं मिल रहे हैं**
- **सड़क ठेका आवंटन और उसके क्रियान्वयन से जुड़ी सार्वजनिक जानकारियां कम आ रही हैं और अनियमित हो गई**
- **नई वेबसाइट शुरू होने के बाद एमआईएस की रिपोर्ट का अद्यतन छह महीने होता था, बाद में यह भी रुक गया**

उद्योग के विशेषज्ञ विगत कई वर्षों से अपना अनुमान जाहिर करने और अन्य रिपोर्टों के लिए ठेका आवंटन और उस पर क्रियान्यवयन की एनएचएआई के आंकड़ों पर ही निर्भर रहे हैं। उन आंकड़ों की मौजूदगी के अभाव में अब उन्हें अन्य खुलासों पर निर्भर होना पड़ रहा है जैसे सूचीबद्ध कंपनियों की ओर से साझा की गई जानकारी और प्रश्न के जवाब में संसद में दिए गए उत्तर आदि।

एक अन्य कर्मचारी ने कहा, 'हम अपने अनुमान और निष्कर्ष सूचीबद्ध स्थानों पर उपलब्ध आंकड़ों के सहारे ही तैयार कर रहे हैं।' कुछ राजमार्ग निर्माण कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं और तिमाही वित्तीय प्रदर्शन का खुलासे के तौर आंकड़े साझा करती हैं।

हालांकि ये कंपनियां विस्तृत आंकड़े तक पहुंचने की अनुमति नहीं देती हैं। इसके अलावा, इक्विरिस कैपिटल की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में असूचीबद्ध कंपनियां एनएचएआई की हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) वाली 63 फीसदी परियोजनाओं को पूरा कर रही थीं। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह आंकड़ा एनएचएआई की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं के मुकाबले 88 फीसदी अधिक है।

आंकड़ों के अद्यतन की गति धीमी पड़ने की वजह स्पष्ट नहीं है। उक्त दूसरे कर्मचारी ने कहा, 'क्रियान्वयन और ठेका आवंटन की धीमी रफ्तार इसके संभावित कारण हो सकते हैं।'

हालांकि इन आंकड़ों की अनुपलब्धता का सड़क डेवलपरों पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। देश के बड़े सड़क डेवलपरों में शामिल एक कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आंकड़ों की अनुपलब्धता कंपनी के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं करते हैं। हालांकि, एनएचएआई के आंकड़ों से राजमार्गों में निवेश की रफ्तार को निर्धारित करने में मदद मिलती है।

साथ में मेघा मनचंदा

बीएस सूडोकू 3604 | परिणाम संख्या 3603

				2	3		8	
	1				6	3	5	7
		9					4	
				8	9	7		5
5		3				8		6
6		7	1	3				
	7					9		
8	3	6	4				7	
	2		3	5				

3	7	5	6	1	4	2	9	8
9	2	6	3	8	7	4	5	1
8	4	1	2	9	5	6	7	3
7	3	2	1	5	6	8	4	9
5	8	9	4	7	2	1	3	6
1	6	4	9	3	8	5	2	7
4	1	8	7	2	3	9	6	5
2	5	3	8	6	9	7	1	4
6	9	7	5	4	1	3	8	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2110/2120, जौ 1790/1800, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1560/1630,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1445, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1535, फ्लैक 1470, डीएमओ 1032, टरपीन लेस बोल्ड 1550

मुजफ्फरनगर
चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3350, सिहोरा 3180, बुंदकी 3240, बुढ़ाना 3290, चीनी हाजिर 3500/3600

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/890, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4250, खल: सरसों 2250/2350,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2140/2150, मक्की 2040/2050, बाजरा 1820/1825, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4590/4600,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3775/3800, जौ 2045/2050, सरसों लूज 3900/3950

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7350/7400, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 5900/6000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बेच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8500, उड़द धोया 9500/10300, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6400/6500, सेला 5600/5700, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4300/4400,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3925/3950, हरियाणा 3900/3925, राजस्थान 3880/3925, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 2180/2190,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4350/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5100, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2500/2600,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2130/2140, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2175/2200, बिहार 2325/2335, दाल उड़द छिलका 9000/10700, चना देशी 5250/5350, दाल चना 5400/5500, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8600, चीन 7400/8000, शर्मिली 5500/6000, किरानाः जीरा 17300/20400, धनिया 7400/10100,

करनाल
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2800/2900, पूसा 1509 धान 2500/2650, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6300/6400,

हिसार
ग्वार 3800/3850, सरसों 4100/4150, गेहूं 2140/2145, नरमा कपास 4900/5000

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4100/4150, खल बिनौला मोटी 2200/2300, बिनौला 2400/3100, सरसों तेल 8750/8800, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 248

प्याज संकट

हाल के वर्षों में मॉनसून के बाद प्याज की कीमतों में बार-बार आने वाली उछाल प्राय: नवंबर तक कम हो जाती थी। परंतु इस वर्ष कीमतें अब तक तेज हैं और निकट भविष्य में उनमें कमी आने की संभावना भी नहीं नजर आती। इसके लिए कुछ हद तक मॉनसून के चलते बुआई और खरीफ की प्याज की फसल लेने में देरी भी वजह है। परंतु सरकार के गलत समय पर किए गए गलत हस्तक्षेप को भी इस संकट के गहराने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। प्याज के निर्यात पर रोक, पादप स्वच्छता और धूम्रीकरण के शिथिल मानकों के साथ प्याज आयात के आपात इंतजाम और प्याज भंडारण की सीमा तय करने जैसे कदमों से यह संकेत गया कि सरकार घबराई हुई है। कमी से उपजे इस डर में और इजाफा करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि असमय हुई बारिश और चक्रवाती तूफानों के कारण प्याज की फसल को 30 से 40 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है। यह राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मसले के कुप्रबंधन के सिवा कुछ नहीं है। अतीत में तो यह सरकार गिरने का कारण तक बन चुका है।

प्याज संकट के बार-बार उभरने की मूल वजह इस हकीकत की अनदेखी करना है कि प्याज की मांग तो साल भर बनी रहती है लेकिन इसकी आपूर्ति मौसमी है। एक तरह से देखा जाए तो हम खुशकिस्मत हैं कि देश में प्याज की फसल तीन बार होती है। खरीफ के आरंभ में, खरीफ के अंत में और रबी के मौसम में। इन तीनों फसलों का प्याज नवंबर से जून के बीच बाजार में आता है। जुलाई से अक्टूबर तक ताजा आपूर्ति नहीं होती है और इस अवधि में बाजार में भंडारित प्याज की बिक्री होती है। ऐसे में प्याज की कीमतों और आपूर्ति प्रबंधन की सबसे अहम बात यह है कि जिस मौसम में ताजे प्याज की आवक नहीं होती है, उस दौरान आपूर्ति के लिए पर्याप्त भंडार रखा जाए। खेद की बात है कि ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि भंडारण को मुनाफाखोरी की वजह से की गई जमाखोरी मानते हुए नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसमें दो राय नहीं कि भंडारण और जमाखोरी के बीच बहुत बारीक अंतर है लेकिन कम से कम प्याज के मामले में इस अंतर को समझना होगा। अनिवार्य जिंस अधिनियम के तहत प्याज भंडारण की सीमा तय करने जैसे कदम और ज्यादा प्याज जमा करने वालों पर छापा मारने जैसे कदमों के चलते कारोबारी और किसान दोनों ही अधिशेष उपज का भंडार करने से बचते हैं। ऐसे उपाय इस वर्ष जल्दी शुरू कर दिए गए जिसका नतीजा आपूर्ति में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया।

जरूरत इस बात की है कि प्याज भंडारण को प्रोत्साहित करके निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्याज का रखरखाव न तो कठिन है, न ही यह लागत की दृष्टि से अच्छा है क्योंकि इसकी प्रकृति खराब होने की है। प्याज को खुली हवादार जगह में रखा जा सकता है। इसके लिए बांस जैसी चीजों का ढांचा बनाया जा सकता है। इसे बारिश से बचाना होगा। कीमतों में मौसमी उछाल को रोकने के लिए जो नीति बने उसमें प्रसंस्करण के जरिये प्याज के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्याज संरक्षण की सबसे सहज और कम लागत वाली तकनीक में प्याज को सुखाना और उसे पेस्ट के रूप में रखना शामिल है। ये उत्पाद उस मौसम में काम आ सकते हैं जब प्याज नहीं होता। उपभोक्ता ताजा या भंडारित प्याज की ऊंची कीमतों से बचने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि प्याज का मौजूदा संकट, सरकार को अतीत की गलतियों से सबक सीखने पर मजबूर करेगा और वह भंडारण एवं प्रसंस्करण जैसे दीर्घकालिक तरीके तलाशेगी।

अजय मोहंती

अर्थव्यवस्था में गिरावट लेकिन बाजार में तेजी

बाजार स्पष्ट रूप से मानता है कि वृद्धि दर 5 फीसदी पर ही नहीं टिकी रहेगी और इसमें जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं आकाश प्रकाश

जब भी मैं उन लोगों से मिलता हूं जो वास्तविक अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, उन्हें यह कभी समझ में नहीं आता कि जब अर्थव्यवस्था संकट में हो तो बाजार नई ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचते हैं। इससे इसी धारणा को बल मिलता है कि बाजार अतार्किक ढंग से काम करते हैं। आखिर अर्थव्यवस्था के 4.5 फीसदी तक लुढ़कने के बाद निफ्टी नई ऊंचाई पर कैसे?

ध्यान रहे कि 4.5 फीसदी का यह आंकड़ा पिछली 26 तिमाहियों का न्यूनतम है और इसमें भी सरकारी व्यय की हिस्सेदारी 1.9 फीसदी है। समायोजित वार्षिक दर के आधार पर जीडीपी केवल 3.6 फीसदी की दर से बढ़ी थी। निजी निवेश न के बराबर है और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की दर बमुश्किल एक फीसदी रही। असमायोजित जीडीपी वृद्धि दर 6.1 फीसदी के नए स्तर तक गिर गई। यह 2019 की दूसरी तिमाही में 12 फीसदी से करीब आधी है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने असमायोजित यानी नॉमिनल जीडीपी के 11.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। ऐसे में राजकोषीय गणित और जटिल हो गया है। सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना नहीं नजर आती। उसके लिए व्यय में भारी कटौती करनी होगी। ऐसी कटौती अर्थव्यवस्था की हालत और पतली करेगी। एक अंक वाली असमायोजित जीडीपी वृद्धि भी कारोबारी आय के लिए प्रतिकूल है क्योंकि लंबी अवधि में जीडीपी और कारोबारी आय के बीच गहन संबंध होते हैं। यानी 6 फीसदी असमायोजित जीडीपी के साथ 20 फीसदी की आय वृद्धि नहीं हासिल की जा सकती। भारत जैसे प्राथमिक घाटे वाले देश के लिए असमायोजित जीडीपी वृद्धि का ऋण की लागत से कम होना उसके ऋण दुष्चक्र में फंसने की वजह बन सकता है। यदि असमायोजित जीडीपी वृद्धि धीमी बनी रहती है तो रेटिंग एजेंसी जल्दी ही दोबारा चिंतित हो जाएंगी। चाहे जैसे भी देखें, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब बनी रहेगी।

ऐसे में बाजार नई ऊंचाई पर कैसे पहुंच रहे हैं? पहली बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हमारे बाजार बहुत अधिक ध्रुवीकृत हैं। कुछ ही शेयर ऐसे हैं जो बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। निफ्टी के नई ऊंचाई पर होने के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपने उच्चतम स्तर से 25 फीसदी और 40 फीसदी नीचे हैं। जाहिर है यह तेजी लार्ज कैप शेयरों की बदौलत है। यहां तक कि निफ्टी 50 सूचकांक में भी समस्त प्रतिफल 15 शेयरों से ही मिले हैं। अगर निफ्टी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो दिसंबर 2015 से शीर्ष 15 शेयरों वाला सूचकांक 40 फीसदी तक उछला जबकि शेष 35 कंपनियों वाला सूचकांक 35 फीसदी नीचे गया है।

यह व्यापक बाजार की बढ़त नहीं है। बुनियादी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया व्यापक आर्थिक गति को प्रदर्शित नहीं करती। बल्कि यह दर्शाती है कि निवेशक किसी भी कीमत पर लार्ज कैप शेयरों में कारोबार करना चाहते हैं। इस असमान वृद्धि में ध्रुवीकरण को आसानी से महसूस किया जा सकता है।

दूसरी बात, वास्तविक अर्थव्यवस्था और बाजार में यह अंतर नया नहीं है। अमेरिका में कहा जाता है कि मेन स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट में अंतर नया नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर बाजार रियायती व्यवस्था पर काम करते हैं। वे प्रमुख आर्थिक संकेतकों की शृंखला का अंग हैं। वे वास्तविक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। बाजारों का कहना है कि वे सबसे बुरा दौर देख चुके हैं और अगले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में नए सिरे से गति देखने को मिलेगी। राजकोषीय और मौद्रिक नीति का सहयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर करेगा और वृद्धि दर में वापसी देखने को मिलेगी। बाजार वृद्धि के सामान्य होने पर दांव लगा रहे हैं। हो सकता है बाजार वृद्धि की वापसी के तरीके को लेकर स्पष्ट न हों लेकिन उन्हें यह साफ पता है कि 5 फीसदी की दर भारत के लिए नव सामान्य नहीं है।

बाजार इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि कमजोर अर्थव्यवस्था गंभीर सुधारों और बदलाव का दबाव बनाएगी। किसी को कॉर्पोरेट कर दर में इतनी कटौती और उसके तत्काल असर की उम्मीद नहीं थी। तमाम लोगों को वास्तविक रणनीतिक विनिवेश की उम्मीद भी नहीं थी लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। बाजार यह मान रहे हैं कि आगामी बजट में व्यक्तिगत कराधान और अन्य ढांचागत सुधारों की दिशा में गंभीर प्रयास देखने को मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी इससे परे नहीं हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कुछ बदलाव करके इसे और सहज बनाया जा सकता है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि वह केवल 5-6 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करे। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि 5 फीसदी की वृद्धि दर के साथ सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए धन नहीं रहेगा। इस दर पर वैश्विक कंपनियां भी भारत में निवेश की इच्छुक नहीं रहेंगी। यदि हम 7-8 फीसदी की दर हासिल नहीं कर सकते तो भारतीय नीति निर्माण की इन अनिश्चितताओं पर चर्चा का मतलब ही क्या है। यदि जल्दी तेजी नहीं आती तो निकट भविष्य में हमारे 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना भी नहीं। यह मंदी बेकार नहीं जाएगी। यही कारण है कि बाजार दांव लगा रहे हैं और शायद सही दांव लगा रहे हैं।

भारतीय बाजार अब अकेले नहीं हैं। दुनिया के तमाम वैश्विक बाजार जोखिम के समक्ष हैं। एसऐंडपी 500 करीब 25 फीसदी ऊपर है और दुनिया भर के बाजार नई ऊंचाई छू रहे हैं। सकारात्मक वैश्विक प्रवाह ने भी बाजारों को ऊपर पहुंचाया है। हालांकि हम नई ऊंचाई पर हैं लेकिन भारतीय बाजारों का प्रदर्शन वैश्विक बाजारों की तुलना में कमजोर रहा है। वैश्विक कारकों के कारण एक सीमा तक भारतीय बाजारों में भी उभार देखने को मिल सकता है। यह स्थानीय कारणों से अलग होगा। बाजार इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वापसी करेगी।

संभव है कि बाजार अग्रगामी हों लेकिन वे अतार्किक कतई नहीं हैं। अगले छह माह कड़ी परीक्षा वाले होंगे। इस अवधि में कुछ न कुछ करना होगा। हमें उपभोक्ता मांग और कारोबारी आत्मविश्वास दोनों बढ़ाना होगा। ऐसे कई सुधार हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि सरकार इस बात से अवगत है कि बाजार दांव लगा रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वृद्धि दर की वापसी होगी। अगर अपेक्षाएं टूटी तो बाजार नकारात्मक भी हो सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का जश्न मनाते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि इन ऊंचाइयों से कितनी उम्मीद जुड़ी हैं। ऐसे में गंभीर सुधारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है। एक व्यवस्थित और सुविचारित योजना के साथ काम करना होगा। सभी का भविष्य इस पर निर्भर है।

बारिश पर ही निर्भर खेती पर ध्यान देने की दरकार

खेती-बाड़ी

सुरिंदर सूद

ऐसी खेती प्रणालियां अपने-आप मौसम एवं मूल्य जोखिम को रोक देती हैं। इससे विपरीत हालात में कम-से-कम किसी काम से तो कमाई हो जाएगी।

भारत के असिंचित या बारिश पर निर्भर कृषि-क्षेत्र के इन आयामों पर गौर करते हैं। कुल फसल-क्षेत्र का करीब 52 फीसदी हिस्सा असिंचित है और वहां खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहती है। देश के 60 फीसदी से अधिक किसान सिंचाई सुविधा के बगैर ही अपनी फसलें उगाते हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के सकल घरेलू उत्पाद (एग्री-जीडीपी) का 55-60 फीसदी हिस्सा बारिश से सिंचित भूभाग से ही आता है। करीब 90 फीसदी ज्वार, बाजरा, रागी एवं अन्य मोटे अनाज, 85 फीसदी दालें, 70 फीसदी तिलहन और 40 फीसदी चावल सिंचाई की सुविधा से रहित खेतों में ही पैदा हो रहे हैं। करीब 65 फीसदी मवेशियों, 75 फीसदी भेड़ों एवं 80 फीसदी बकरियों की देखभाल बारिश पर निर्भर किसान ही कर रहे हैं।

काफी खेदजनक है कि कृषि के इतने अहम पहलू को विकास प्रक्रिया में जरूरी तवज्जो नहीं दी गई है। निवेश एवं प्रोत्साहक प्रयासों का बड़ा हिस्सा पानी-आधारित खेती तक ही सीमित रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत में सिंचित खेती को अध्यारोही प्राथमिकता देना तो समझा जा सकता है। उस समय खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि अपने संसाधनों एवं प्रयासों को उन्हीं इलाकों तक केंद्रित रखा जाए कि उपज में फौरी राहत हासिल हो। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में आधिक्य के बाद भी उसी रणनीति पर टिके रहने को सही ठहरा पाना मुश्किल है।

इस भेदभाव का वास्तविक नतीजा यह हुआ है कि बारिश-आश्रित इलाकों में औसत फसल उपज प्रति हेक्टेयर सिर्फ 1.1 टन रह गया है जबकि यह सिंचाई सुविधा वाले इलाकों में 2.8 टन से अधिक हो चुका है। प्रगतिशील किसान आम तौर पर सिंचित खेत से प्रति हेक्टेयर 4-6 टन अनाज की ही फसल उगाते हैं। बारिश पर निर्भर इलाकों को संबद्ध सेवाएं खासकर मार्केटिंग मदद मुहैया कराने में नजरअंदाज किया गया है जिससे उनकी आर्थिक संवहनीयता पर गहरी चोट पहुंची है। बारिश पर आश्रित किसानों की केवल 20-30 फीसदी आय ही फसल उगाने से होती है। बाकी आय मवेशियों की देखभाल एवं दूसरे साधनों से होती है।

इसके उलट सिंचाई सुविधायुक्त खेतों की जुताई करने वाले किसान अपनी आय का करीब 60 फीसदी हिस्सा फसलों से ही जुटा लेते हैं। ऐसे में अचरज नहीं है कि हरित क्रांति काफी हद तक गेहूं, चावल, गन्ना एवं कुछ अन्य सिंचित उपजों तक ही सीमित रहा है। प्रमुख रूप से सूखी जमीन वाली फसलों, मसलन तिलहन, दाल एवं मोटे अनाज, बेहद पौष्टिक माने जाने वाले मोटे अनाजों को इससे खास फायदा नहीं हुआ है। इसे अब और जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की तवज्जो बारिश पर आश्रित इलाकों पर केंद्रित करने की जरूरत है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन्हीं इलाकों में ग्रामीण गरीबों की बड़ी आबादी रहती है।

बड़े एवं नजदीकी शुष्क-खेती वाले इलाकों से हर कोई परिचित है। ऐसे अधिकांश इलाके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य राजस्थान, सौराष्ट्र एवं पश्चिमी घाटों के कुछ क्षेत्रों में हैं। कई अन्य राज्यों में भी सिंचाई से वंचित जमीनों का बड़ा हिस्सा है।

बारिश पर निर्भर इन इलाकों में आम तौर पर छोटे एवं सीमांत जोत वाले किसान ही हैं। वहां पर मृदा अपरदन, क्षरण एवं निम्न उत्पादन की समस्या भी है। भूजल या तो उपलब्ध ही नहीं है या फिर उसकी गुणवत्ता खराब है और ढांचा भी अपर्याप्त है। इन कृषि-क्षेत्रों के किसानों के पास नकदी की भारी किल्लत होती है और उनकी उम्र भी अधिक हो चुकी है क्योंकि युवा पीढ़ी अब कामकाज की तलाश में दूसरी जगहों पर चली जा रही है। इन क्षेत्रों के कृषि-पारिस्थितिकीय हालात काफी अलग हैं और जलवायु परिवर्तन के चलते स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है। इस तरह इन इलाकों में कृषि को उन्नत बनाने के लिए क्षेत्र-केंद्रित रणनीति की जरूरत है।

बारिश पर निर्भर खेती की हालत सुधारने के लिए गत दिनों दिल्ली में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कई मूल्यवान सुझाव सामने आए। यह सम्मेलन 'जलवायु-सजग कृषि के लिए मृदा एवं जल संसाधन प्रबंधन' विषय पर आयोजित किया गया था। वहां जल संरक्षण में नाकामी एवं समुचित एकीकृत खेती प्रणालियों के प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बारिश से सिंचित होने वाले इलाकों में खेती करते समय फसलें उगाने के साथ पेड़ लगाने, पशुपालन, मत्स्यपालन और मधुमक्खी-पालन जैसे संबद्ध काम करने की जरूरत है ताकि उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। ऐसी खेती प्रणालियां अपने-आप मौसम एवं मूल्य जोखिमों को रोक देती हैं। इससे विपरीत हालात में कम-से-कम किसी काम से तो कमाई हो जाएगी।

किसानों की उत्पादक कंपनियों के गठन को प्रोत्साहन देने से भी कृषि उत्पादन में लगने वाले उत्पादों की खरीद एवं तैयार उपज की बिक्री बेहतर दरों पर की जा सकेगी। ये इकाइयां खेती में नई तकनीकों एवं मशीनों के इस्तेमाल में सहयोगी साबित हो सकती हैं। हालांकि इनमें से कोई भी तरीका कृषि शोध केंद्रों के समुचित समर्थन के बगैर कारगर नहीं हो सकता है। हालात के हिसाब से तकनीकों का इस्तेमाल ही कम लागत पर अधिक उपज दिला सकता है। बारिश पर निर्भर किसानों के लिए खेती को मुनाफे का जरिया बनाने के लिए यह निहायत ही जरूरी है।

कानाफूसी

वक्त है बदलाव का

मध्य प्रदेश में जल्दी ही प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल की जगह किसी अन्य करीबी अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। बर्णवाल प्रदेश की पिछली सरकार में भी इस पद पर थे और कमल नाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक वर्ष तक इस कुर्सी पर बने रहे। अब उन्हें किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसा कि हमने इस स्तंभ में बुधवार को भी लिखा था, प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए पी श्रीवास्तव के बीच ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे हैं। श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह सिंघार के साथ काम करने को लेकर सहज नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्हें वित्त विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्रियंका की सक्रियता

ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस आरोप को गलत साबित करने की ठान ली है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका सोशल मीडिया पर ही मुद्दे उठाती हैं। आगामी 14 दिसंबर को पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ आयोजित रैली की निगरानी के लिए प्रियंका लखनऊ में डेरा डाल रही हैं। रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा और यह आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसानों की निराशा, मुद्रास्फीति आदि पर केंद्रित होगी। राज्य इकाई के सदस्य बड़ी तादाद में इस रैली में शामिल हों, यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी स्वयंसेवकों का एक दल तैयार कर रही है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है।

आपका पक्ष

रोजगार सृजन के लिए सामूहिक प्रयास

बेरोजगारी देश के लिए सिरदर्द बन गई है और इसके कारण करोड़ों युवाओं को घर पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। देश में बेरोजगारी की समस्या कोई नई नहीं है। गरीबी हटाओ का अभियान आज से लगभग 45 वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। लेकिन आज 21वीं सदी में बेरोजगारी अपनी जड़ बहुत मजबूत कर चुकी है। लेकिन जिस तरह इसके उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं उससे लगता है कि यह उन्मूलन इतना आसान नहीं है। एक युवक के बेरोजगार रहने से न सिर्फ उस युवक के रहन-सहन पर असर पड़ता है बल्कि उसपर आश्रित पूरे परिवार को निम्न स्तर की जिंदगी भी नसीब नहीं हो पाती है। अक्टूबर में बेरोजगारी की दर 8.5 फीसदी हो गई है जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। बेरोजगारी की दर अगस्त 2016 के बाद सबसे अधिक है। यह सितंबर के मुकाबले 7.2 फीसदी ज्यादा है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है। देश में जो हालात हैं उसमें बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, कौशल की कमी, प्रदर्शन संबंधी मुद्दे और बढ़ती आबादी सहित कई कारक बेरोजगारी को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं।

देश में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है। इस संबंध में ठोस कदम उठाने होंगे।

इस कारण देश के जीडीपी पर भी साफ असर दिख रहा है। बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक-आर्थिक मसले होते हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ हद तक कदम भी उठाए हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नीति निर्माताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के सृजन के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।

अनु मिश्रा, सीवान

समाज में मातृ शक्ति भावना की जरूरत

हैदराबाद में पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना ने फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी है। निर्भया कांड के बाद कई कानून भी बने लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि शासन- प्रशासन को जो करना है वह करेगी लेकिन उन्हीं पर सबकुछ छोड़ दिया जाए तो हम एक सुरक्षित समाज की कल्पना के अलावा जमीनी हकीकत पर नहीं ला सकते हैं। इसलिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में खुद से शुरुआत करनी होगी। किसी की बेटी, मां, बच्ची से खुद भी एक बहन जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। समाज में अगर मातृ शक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए तो अपने आप बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। अगर ऐसी ही घटनाएं होती रहीं तो हमारा समाज बेटियों को पूर्ण रूप से नहीं चाहेगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बेटियां एक सिक्के की पहलू हैं। जिस प्रकार सिक्के का एक पहलू नहीं होने पर सिक्का अपर्याप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा समाज भी बेटियों के बिना उजड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने विचार को बदलने तथा मातृ शक्ति की भावना लाने की जरूरत है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

प्याज : कच्ची फसल ही काट रहे किसान

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 4 दिसंबर

नए सत्र की आवक शुरू होने के साथ ही महाराष्ट्र के नाशिक जिले के किसानों ने मंडियों में प्याज के अधिक दाम प्राप्त करने के लिए अपरिपक्व फसल की कटाई शुरू कर दी है। किसानों को इस बात का डर है कि आयात बढ़ने और स्थानीय स्रोतों से आवक में इजाफा होने की वजह से प्याज के दामों में गिरावट आने लगेगी। यही कारण है कि किसान इससे पहले ही अपरिपक्व प्याज बेचकर अधिक दामों का लाभ उठाना चाहते हैं।

महाराष्ट्र के नाशिक जिले में एशिया के सबसे बड़े प्याज बिक्री केंद्र लासलगांव मंडी में बुधवार को अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के दाम 93.50 रुपये प्रति किलोग्राम बोले गए हैं। मंगलवार को प्रचलित दामों की तुलना में इनमें प्रति किलोग्राम 2.60 रुपये का इजाफा हुआ है। हालांकि सबसे खराब गुणवत्ता वाला प्याज बुधवार को प्रति किलोग्राम 25.50 रुपये की दर पर बिक रहा था, जबकि मंगलवार को इसके दाम प्रति किलोग्राम 20 रुपये थे। इस तरह लासलगांव थोक बिक्री मंडी में प्याज के आदर्श दाम 70 से 75 रुपये प्रति किलोग्राम बैठते हैं। देश भर के खुदरा बाजारों में दाम 100 से 125 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। हालांकि 2019 की शुरुआत में नासिक की थोक मंडियों में प्याज के दाम दो से तीन रुपये प्रति किलोग्राम के आस-पास चल रहे थे।

लासलगांव मंडी के चेयरमैन जयदत्त होल्कर ने कहा कि राजस्थान से आने वाली शुरुआती फसल की आवक इस साल कुछ ही सप्ताहों में समाप्त हो गई। अत्यधिक बारिश की वजह से प्रमुख उत्पादक राज्यों, खास तौर पर महाराष्ट्र में फसल को हुए नुकसान की सूचना मिलने के कारण किसान मंडियों में बेचने के लिए अपरिपक्व या बिना पकी फसल ला रहे हैं। लासलगांव मंडी की कुल आवक का लगभग 25 प्रतिशत भाग मौजूदा सत्र के अपरिपक्व या बिना पके प्याज का है।

बुधवार को लासलगांव मंडी में प्याज आवक केवल 400 टन (करीब 1-1 टन वाले 400 ट्रक) के आस-पास ही दर्ज की गई, जबकि मंगलवार को आवक 440 टन थी। मौजूदा आवक की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि फसल कटाई के शीर्ष समय में लासलगांव मंडी में प्रतिदिन करीब 22,000 टन से लेकर 25,000 टन तक की आवक होती है। नासिक में प्याज के थोक विक्रेता संजय सनप ने कहा कि चूंकि सरकार ने स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं पर स्टॉक सीमा लगाई हुई है, इसलिए किसान खराब होने से बचाने के लिए सीमित मात्रा में नई फसल ला रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारी नमी कम करने तथा अधिक दाम प्राप्त करने के लिए अपना खरीदा हुआ प्याज धूप में सुखा रहे हैं।

देश का वार्षिक प्याज उत्पादन तकरीबन 2.3 करोड़ टन रहने का अनुमान है। सालाना 30 लाख से 40 लाख टन के बीच निर्यात किए जाने के कारण देश का प्याज उपभोग 1.9 करोड़ से दो करोड़ टन रहने की संभावना है।

बढ़ते दाम भुनाने की कवायद में किसान

- प्याज के दामों में इजाफे का फायदा उठाने को किसान काट रहे अपरिपक्व या बिना पकी फसल
- लासलगांव मंडी में तकरीबन 25 प्रतिशत आवक हो रही खराब गुणवत्ता वाले अपरिपक्व प्याज की

प. बंगाल सरकार ने दिया 800 टन प्याज का ऑर्डर

पश्चिम बंगाल सरकार ने मिस्र से 800 टन प्याज आयात के लिए नेफेड को ऑर्डर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि उसे यह खेप दिसंबर अंत तक मिल जानी चाहिए ताकि राज्य में प्याज की उचित दाम पर आपूर्ति की जा सके। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने प्याज आयात का यह ऑर्डर मुंबई बंदरगाह तक पहुंचाकर 55 रुपये किलो के भाव पर दिया है। यह आर्डर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) के जरिये मंगाया जा रहा है और उसी को इसका वितरण करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने कुल 800 टन प्याज के आयात का आर्डर दिया है जिसमें से 200 टन प्रति सप्ताह के हिसाब से खेप दिसंबर माह में ही आ जाएगी। मुंबई बंदरगाह पर आकर इसकी लागत 55 रुपये किलो पड़ेगी और वहां से कोलकाता पहुंचते पहुंचते यह प्याज 65 रुपये किलो तक पड़ जाएगा। प्याज का आयात मिस्र से किया जा रहा है। *भाषा*

अफगानिस्तान से अटारी-वाघा बॉर्डर होते हुए प्याज मंगा रहे व्यापारी

दिल्ली और पंजाब के व्यापारी अफगानिस्तान से प्याज का आयात कर रहे हैं। अटारी-वाघा बॉर्डर से होता हुआ 10 से 15 ट्रक प्याज रोजाना अमृतसर पहुंच रहा है। व्यापारी संघ ने यह जानकारी दी है। फेडरेशन आफ किरयाना ऐंड ड्राई फ्रुट कमर्शियल एसोसिएशनन के अनिल मेहरा ने यहां बताया कि प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान से दस से पंद्रह ट्रक प्याज हर रोज अमृतसर पहुंच रहा है। पंजाब और दिल्ली के व्यापारी यह आयात कर रहे हैं। इसकी उत्तर भारत के बाजारों में आपूर्ति की जा रही है। मेहरा का कहना है कि अफगानिस्तान से आयातित प्याज खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। *भाषा*

नए साल की दूसरी छमाही तक सुस्त रहेगी डीजल की मांग

रॉयटर्स
नई दिल्ली/मुंबई, 4 दिसंबर

भारत में डीजल की मांग 2020 की दूसरी छमाही तक सुस्त बनी रहेगी। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि उसके बाद औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए किए गए तमाम नीतिगत उपायों के परिणाम आने लगेंगे और अधिक ईंधन की खपत होगी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार घटकर छह साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में जब तक भारत में खपत जोर नहीं पकड़ती है रिफाइनर कभी कभी होने वाले डीजल निर्यातों के हालिया खंड को और आगे बढ़ा सकते हैं जिससे इस क्षेत्र में रिफाइनिंग मार्जिन पर असर पड़ा है।

भारत में रिफाइंड ईंधन की मांग में डीजल की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है जो वित्त वर्ष 2014 से इस साल तक सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। इसकी वजह सख्त क्रेडिट मार्केट, वाहनों की घटती बिक्री और रेल व हवाई यातायात में आ रही कमी है।

सरकारी रिफाइनर के एक अधिकारी ने कहा कि 2019-20 वित्त वर्ष में डीजल निर्यात में 80 लाख टन तक की उछाल आ सकती है जबकि एक वर्ष पहले 2.8 करोड़ टन का निर्यात हुआ था। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली कंपनी रिफाइनिटीव की ओर से संग्रहीत डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2018 से इस साल अप्रैल में वित्त वर्ष की शुरुआत तक भारत के डीजल निर्यात में 8.9 फीसदी की उछाल आ चुकी है और यह 1.77 करोड़ टन हो गई है। यह 2015 के बाद से उस दौरान सर्वाधिक रहा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 वित्त वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 8.35 करोड़ टन डीजल का उपभोग किया और यह उसके पिछले वर्ष से 3 फीसदी अधिक है।

मूडीज की स्थानीय इकाई इक्रा लिमिटेड में कॉर्पोरेट खंड रेटिंग्स के समूह प्रमुख के रविचंद्रण के मुताबिक 2019-20 में मांग की वृद्धि दर सपाट या 1 फीसदी रह सकती है।

फिच की स्थानीय यूनिट इंडिया रेटिंग्स में तेल और गैस विश्लेषक भानू पाटनी ने कहा कि अगले कई महीनों तक डीजल की खपत में कमी आती रहेगी। उन्होंने कहा, '2020 की पहली छमाही से पहले डीजल की खपत में सुधार नहीं होगा।' सरकार ने उत्पादन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर में कॉर्पोरेट कर की दरों में कटोती की घोषणा की थी, वहीं केंद्रीय बैंक ने भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के मद्देनजर ब्याज दरों में कटौती की लेकिन इनसे अभी तक मांग में वृद्धि नहीं हुई है।

भारत सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए फैक्टरी उत्पादन के आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन उस महीने डीजल खपत में आई 7.4 फीसदी की गिरावट से पता चलता है कि देश का औद्योगिक इंजन लगातार सुस्त पड़ा हुआ है। उस महीने डीजल खपत तीन साल में सबसे कम रहा। मॉनसूनी बारिश का समय लंबा खिंचने से भी डीजल की मांग को धक्का लगा है। मॉनसूनी बारिश होने से खेती के लिए डीजल की खपत में कमी आई और सितंबर से ग्रामीण निर्माण कार्य बाधित हो गया।

सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों के अधिक इस्तेमाल ने भी कृषि क्षेत्र में डीजल की मांग को चोट पहुंचाई है, वहीं डीजल के बजाय गैसोलीन से चलने वाले कारों के इस्तेमाल के प्रति लगातार बढ़ते रुझान से भी डीजल की खपत मंद पड़ी है। भारत में छाई आर्थिक सुस्ती के कारण भी तेल की मांग घटी है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 4	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,802.0	3.9	1,887.3	-3.5
Copper	5,812.0	2.6	6,207.2	1.7
Nickel	13,600.0	-24.1	14,119.9	-22.9
Lead	1,883.5	-7.2	2,125.0	5.0
Tin	16,750.0	-1.2	17,475.2	-0.4
Zinc	2,221.5	-2.1	2,572.3	0.8
Gold ($/ounce)	1,476.8*	-4.9	1,660.3	-1.4
Silver ($/ounce)	17.2*	-12.5	19.4	-9.8
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	61.8*	1.9	61.9	6.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.4*	-2.4	2.4	-0.7
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	186.9	15.1	298.8	5.9
Maize	183.6*	3.2	314.4	7.1
Sugar	346.3*	14.2	483.3	-1.3
Palm oil	660.0	23.4	1,041.5	21.2
Rubber	1,545.8*	0.0	1,817.4	-6.4
Coffee Robusta	1,374.0*	6.7	1,880.3	-9.9
Cotton	1,391.1	7.4	1,564.1	-1.3

* As on Dec 04, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.5& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	31.4	11834
Oil and Oilseeds	188.5	67882
Spices	1.8	14
Metal(Dec 03)		
Metal- non ferrous	6535.7	64775
Metal- precious	11193.5	418
Oil and gas(Dec 03)		
Gas	3478.4	37969
Oil	15454.1	2112

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	112.4	111526
Grains	164.2	102665
Oil and Oilseeds	553.1	495760
Others	125.3	68660
Pulses	115.2	64325
Spices	96.9	32015

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Dec 26)	179.7	7.0
Cardamom (Dec 13)	2915.4	2.9
Silver Mini (Feb 28)	45314.0	1.3
Silver Micro (Feb 28)	45314.0	1.2
Gold Mini (Dec 05)	38267.0	0.9
Gold (Dec 05)	38250.0	0.8
Losers (* % Change)		
Nickel (Dec 31)	986.4	-2.3
Copper (Dec 31)	428.4	-0.9
Aluminium (Dec 31)	133.6	-0.8
Aluminium Mini (Dec 31)	133.6	-0.7
Zinc (Dec 31)	181.5	-0.4
Zinc Mini (Dec 31)	182.0	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Maize Kharif (Dec 20)	2032.0	3.1
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4034.0	1.3
Coriander-Kota (Dec 20)	6596.0	0.9
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	1942.0	0.8
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	829.0	0.6
Soyabean Indore (Dec 20)	4106.0	0.1
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Dec 20)	15815.0	-1.9
Guar Seed 10 (Dec 20)	3966.0	-1.6
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7142.0	-1.3
Chana-Bikaner (Dec 20)	4404.0	-1.2
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5592.0	-0.9
Barley Jaipur (Apr 20)	1680.0	-0.7

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	4.5
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	2915.4	2.8
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19020.0	2.1
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	45314.0	1.4
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3888.0	1.4
Gold Ahm (Dec 05)	38250.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1298.0	-7.8
Aluminium Mum (Dec 31)	133.6	-5.1
Alumini-Mumbai (Dec 31)	133.6	-5.1
Copper Mum (Dec 31)	428.4	-3.7
Lead Mum (Dec 31)	152.4	-2.7
Lead Min Mumbai (Dec 31)	152.5	-2.7

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Maize-Sangli (Dec 20)	2032.0	1.6
Soy Bean Indore (Dec 20)	4106.0	0.6
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18580.0	0.6
Barley Jaipur (Dec 20)	2127.5	0.5
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3108.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5592.0	-5.2
Coriander-Kota (Dec 20)	6596.0	-4.1
Jeera Unjha (Dec 20)	15815.0	-3.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7142.0	-2.2
Moong-Merta City (Dec 20)	6600.0	-2.0
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	686.2	-0.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98(98)
Aluminium ingots /kg	135(135)
Brass sheet cutting /kg	313(314)
Brass utensil scraps/kg	296(295)
Copper heavy scrap /kg	412(413)
Copper utensil scraps/kg	387(389)
Copper wire bar /kg	444(445)
Lead ingots /kg	152(152)
Nickel Cathodes /kg	1010(1030)
Tin slabs /kg	1250(1240)
Zinc slabs /kg	184(185)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10714(10714)
DCH - 32 /Qtl	11360(11360)
Jaydhar /Qtl	10011(10011)
Shankar- 6 /Qtl	11220(11220)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	855(863)
Castor Comm /10kg	845(853)
Ricebran oil/10kg	760(760)
Groundnut oil /10kg	1020(1020)
Linseed oil /10kg	845(845)
Karanji /10kg	760(760)
Palm oil /10kg	768(762)
Sunflower exp ref /10kg	830(830)
Sunflower oil exp /10kg	790(790)
Soyabean ref / 10kg	810(810)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3332-3582 (3352-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	56.98(56.1)
Brent Crude (UK)	61.73(60.94)
Brent Crude (WTI)	56.1(56.1)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.4(2.44)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	239.27(232.58)
Naptha spot /Rs/MT	45170(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38184(38111)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38338(38265)
Silver.999/ kg	44700(44560)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18529.80	18467.00
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.60	140.80
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1895.00	1895.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2121.75	2117.95
Brass-Jamnagar (M)	1 K	299.50	312.50
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2925.00	2883.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4036.65	4084.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	3975.00	3987.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4337.20	4307.65
Chana Delhi (N)	1 Q	4522.50	4500.00
Chana-Akola (N)	X	4550.00	4428.15
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6833.35	6812.50
Coriander-Kota (N)	1 Q	6916.25	6875.90
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2009.60	1996.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1925.00	1950.00
Cotton-Kadi (N)	1 B	18453.30	18465.25
CPO-Kandla (M)	10 K	683.00	687.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	683.25	687.45
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	882.00	886.50
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1539.75	1543.05
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3471.75	3480.45
Gold Ahm (M)	10 G	38062.00	38162.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30572.00	30652.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3825.00	3833.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7407.30	7298.95
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4001.25	3948.35
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3925.00	3900.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1017.85	1017.85
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.70	93.60
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17000.00	16850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16409.50	16355.25
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1002.55	1007.80
Kapas-Rajkot (N)	X	991.60	993.50
Lead Mum (M)	1 K	155.00	156.70
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1905.00	1910.65
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2242.35	2230.00
Maize-Erode (N)	X	2100.00	2103.75
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2120.00	2150.00
Maize-Sangli (N)	X	1967.10	2000.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	6719.45	6737.50
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4540.00	4565.75
Nickel Mumbai (M)	1 K	1030.40	1010.10
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3153.00	3187.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	350.00	350.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35125.00	35026.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	785.00	787.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2100.85	2100.50
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	746.25	745.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	821.70	826.15
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	805.85	819.55
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	824.50	825.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13062.50	13000.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13050.00	13025.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44437.00	44671.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4091.00	4081.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4007.50	4007.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4070.30	4090.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4275.00	4108.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33700.00	33500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	822.50	824.80
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	28000.00	27910.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29100.00	29040.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26060.00	26000.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3285.00	3280.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3364.60	3380.95
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3282.50	3296.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3447.60	3438.10
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3301.10	3285.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3134.15	3130.45
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5907.15	5900.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2258.75	2250.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2131.40	2124.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2073.75	2073.75
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2200.00	2191.25
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4650.00	4704.60
Zinc Mumbai (M)	1 K	185.00	184.20

* as on Dec 03, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (बुधवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19050, 19060, 18950, 19020	2326	370	8975
Jan 31	19200, 19210, 19120, 19200	323	67	2147
May 29	20340, 20340, 20340, 20340	04	1	04
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	1933, 1960, 1929, 1942	17230	1117	36730
Jan 20	1945, 1980, 1945, 1961	25520	1782	47100
Feb 20	1968, 1996, 1965, 1986	6280	495	21510
Mar 20	2001, 2021, 1992, 2010	520	42	2370
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1068, 1068.5, 1059.5, 1065.5	328	70	644
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1067, 1068, 1061.5, 1066.5	714	385	3816
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1680, 1680, 1680, 1680	100	1	520
May 20	1695, 1695, 1695, 1695	200	2	610
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4020, 4042, 3952, 3966	12830	1649	35310
Jan 20	4042, 4064, 3980, 3994	27095	3209	61305
Feb 20	4080, 4092, 4018, 4026	770	123	1320
Maize Kharif NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	2025, 2032, 2025, 2032	1600	10	3600
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	3962, 4046, 3962, 4034	9645	705	26935
Jan 20	3996, 4088, 3996, 4078	4685	551	22495
Feb 20	4014, 4050, 4014, 4050	80	8	3740
Mar 20	4040, 4070, 4038, 4042	110	11	2865
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	682.1, 689.7, 681.2, 688.2	15060	1000	48130
Jan 31	682.5, 690, 682, 688.4	7240	494	18250
Feb 28	687, 694.1, 685.5, 693	880	86	1210
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1297, 1304.8, 1292.6, 1298	208.8	483	267.48
Jan 31	1302, 1310, 1302, 1307.5	16.92	29	24.48
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4366, 4377, 4346, 4363	6140	495	23740
Jan 20	4401, 4408, 4382, 4393	4860	397	7140
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	825, 830.6, 822.2, 829	8910	939	25860
Jan 20	828, 833, 826, 830.6	11170	1005	46625
Feb 20	822.6, 829.6, 822.4, 829.2	2705	200	12725
Mar 20	819, 826, 819, 826	15	3	35
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4110, 4126, 4080, 4106	20075	2349	54850
Jan 20	4154, 4154, 4106, 4136	29455	3411	151295
Feb 20	4154, 4172, 4128, 4156	9255	1046	89935
Mar 20	4180, 4194, 4156, 4184	3670	512	26065
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7212, 7255, 7115, 7142	6730	967	16570
Jan 20	7302, 7358, 7220, 7242	9805	1463	51160
Feb 20	7404, 7453, 7324, 7345	715	93	880
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4465, 4465, 4351, 4404	10760	739	26030
Jan 20	4488, 4488, 4421, 4431	14820	1109	35460
Mar 20	4382, 4399, 4380, 4390	230	23	2350
Apr 20	4353, 4360, 4340, 4351	170	16	410
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	2853, 2920, 2853, 2915.4	1.6	16	2
Jan 15	2751, 2870, 2750, 2840.3	4.5	45	9.8
Feb 14	2733.4, 2735, 2733.4, 2734.2	0.2	2	1.5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6369, 6665, 6369, 6596	1680	147	7020
Jan 20	6384, 6672, 6384, 6519	1570	137	5900
Apr 20	6911, 6935, 6865, 6897	270	26	2600
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16165, 16390, 15715, 15815	2070	528	1773
Jan 20	16025, 16025, 15740, 15810	1173	353	1791
Mar 20	15790, 15795, 15725, 15755	48	16	210
Apr 20	15900, 15900, 15900, 15900	6	2	6
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5650, 5650, 5556, 5592	2115	366	8315
Mar 20	5970, 6014, 5870, 5880	1110	199	2820
Apr 20	6020, 6028, 5904, 5910	500	88	1575

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.55, 133.8, 132.65, 133.65	4585	735	8245
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.5, 133.7, 132.65, 133.6	2127	1786	3117
Jan 31	134.6, 134.65, 133.85, 134.45	135	107	309
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	429.3, 431, 427.7, 430.3	17220	5755	17665
Jan 31	433.95, 435.9, 432.7, 435.2	335	124	825
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.55, 153.35, 151.8, 152.95	12765	2078	6915
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.55, 153.35, 152.05, 153	4859	4041	3212
Jan 31	152.8, 153.5, 152.4, 153.1	76	73	120
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	979.4, 987.7, 976.2, 984.6	10156.5	6038	3508.5
Jan 31	978, 985.9, 974.4, 984	93	60	205.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	181.75, 184.3, 181.65, 183.45	35180	5570	18505

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.6, 184.65, 182.15, 183.85	10310	8231	5508
Jan 31	182.85, 184.15, 182.1, 183.5	801	585	1127
Feb 28	183.5, 184, 183.5, 183.75	2	2	3
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	38331, 38450, 38285, 38330	0.05	43	0.09
Feb 05	38330, 38467, 38121, 38186	8.43	7108	17.8
Apr 03	38386, 38498, 38172, 38244	0.18	167	1.86
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30701, 30825, 30650, 30711	0	366	0.01
Jan 31	30649, 30725, 30611, 30670	0	23	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	38563, 38563, 38116, 38278	0	23	0.04
Jan 03	38344, 38460, 38150, 38209	1.03	8650	0.91
Feb 05	38301, 38464, 38129, 38199	0.2	1680	0.2
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3888, 3900, 3880, 3886	0	969	0.01
Jan 31	3880, 3900, 3865, 3870	0	219	0
Feb 28	3870, 3870, 3866, 3868	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44949, 45100, 44715, 44946	0.54	15	6.21
Mar 05	45361, 45678, 45129, 45183	400.74	10795	315.36
May 05	45874, 46169, 45625, 45696	3.93	127	3.69
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45315, 45687, 45153, 45215	33.72	22191	24.28
Apr 30	45900, 46173, 45643, 45712	1.07	853	1.13
Jun 30	45711, 47899, 45711, 46805	0	2	0
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45260, 45690, 45150, 45210	105.21	16642	46.68
Apr 30	45916, 46161, 45633, 45745	1.14	207	1.04

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	177.5, 177.5, 171.2, 172.5	87294mb	39963	35175mb
Jan 28	176.7, 176.7, 170.3, 171.4	7290mb	3690	8966mb
Feb 25	169.5, 169.8, 165.5, 166.7	724mb	482	1676mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4048, 4090, 4041, 4075	9897bl	48417	2747bl
Jan 17	4062, 4097, 4050, 4081	210bl	1600	143bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4042, 4090, 4041, 4076	2088bl	81580	594bl

सायं सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19070, 19110, 19020, 19060	2224	327	8992
Jan 31	19230, 19250, 19200, 19220	259	41	2028
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1072, 1073, 1066.5, 1068	144	36	604
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1071, 1072.5, 1065, 1066.5	591	294	3810
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	682.8, 685.2, 679.5, 682.1	20270	1273	50180
Jan 31	682.7, 685.3, 679.3, 681.8	8500	614	14920
Feb 28	685.1, 690, 684.5, 685.9	510	44	630
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	821, 827.6, 821, 823.2	10090	1188	26920
Jan 20	823.6, 831.6, 823.4, 826.4	14775	1338	46335
Feb 20	821.6, 829, 821.6, 824	3645	159	10815

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	134.5, 134.9, 133.3, 133.55	13105	1819	7825
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	134.5, 134.9, 133.3, 133.6	4575	3763	2798
Jan 31	135.2, 135.7, 134.4, 134.65	285	226	251
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	432.4, 432.6, 428.2, 428.35	31822.5	10452	16125
Jan 31	437.3, 437.45, 433, 433.3	567.5	217	750
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.4, 152.9, 151.6, 152.4	25955	4023	5980
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.5, 152.85, 151.7, 152.45	10014	7815	2867
Jan 31	152.7, 153.1, 152.05, 152.6	194	180	85
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1012.4, 1013.8, 973.7, 986.4	28158	16207	2217
Jan 31	1009.5, 1010, 972.5, 981.7	361.5	236	187.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.8, 182.8, 180.55, 181.45	61250	9759	19080
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183, 183, 181.1, 182	20930	15534	5792
Jan 31	183.5, 183.5, 181.5, 182.1	945	722	814
Feb 28	183.05, 183.5, 183, 183.15	4	4	3
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	37930, 38768, 37880, 38250	0.05	32	0.1
Feb 05	37881, 38392, 37825, 38327	15.81	13225	17.71
Apr 03	37902, 38434, 37855, 38384	0.22	203	1.79
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30534, 30750, 30480, 30712	0.01	569	0
Jan 31	30485, 30695, 30485, 30672	0	27	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	37874, 38400, 37840, 38267	0.01	60	0.06
Jan 03	37949, 38378, 37879, 38337	1.88	15557	0.91
Feb 05	37910, 38388, 37843, 38334	0.35	2916	0.18
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3860, 3895, 3859, 3888	0.01	1867	0.01
Jan 31	3857, 3890, 3831, 3876	0	450	0
Feb 28	3883, 3888, 3883, 3886	0	10	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44250, 44985, 44150, 44620	4.14	44	10.53
Mar 05	44684, 45473, 44590, 45294	664.98	17972	317.4
May 05	45263, 45934, 45263, 45829	1.77	59	2.64
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44740, 45481, 44621, 45314	64.45	41946	23.16
Apr 30	45240, 45960, 45123, 45788	2.15	1700	0.98
Aug 31	48879, 48880, 46000, 48160	0	4	0
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44823, 45487, 44620, 45314	193.7	31149	41.19
Apr 30	45205, 45950, 45132, 45800	1.83	335	0.83
Jun 30	45065, 45065, 45065, 45065	0.01	1	0.02

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	169, 180.5, 168.4, 179.7	183470mb	82934	28634mb
Jan 28	168.5, 178.4, 167.8, 177.7	15114mb	7426	7831mb
Feb 25	164.3, 172, 163.9, 171.4	1558mb	1051	1504mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4025, 4047, 3973, 4039	31350bl	151982	1601bl
Jan 17	4036, 4054, 3985, 4048	587bl	4573	131bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4020, 4048, 3974, 4039	6564bl	242402	380bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

उद्योग में सफेदपोश अपराधों की सेंध

एक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त, दवा और आईटी आदि क्षेत्रों में धोखाधड़ी, गबन जैसे मामले बढ़े

रुचिका चित्रवंशी

सभी उद्योगों विशेष रूप से वित्तीय, दवा, सूचना तकनीक और विनिर्माण में व्हाइट कॉलर (सफेदपोश) अपराधों ने सेंध लगा ली है। नेट्रिका कंसल्टिंग और इंडियन नैशनल बार एसोसिएशन के एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक इन क्षेत्रों में धन शोधन, कर चोरी, गबन, प्रतिभूति, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में धोखाधड़ी के कुल 3,766 मामले पकड़े गए हैं। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018 की तुलना में 15 फीसदी अधिक है। इसके अलावा धोखाधड़ी की वजह से होने वाले नुकसान में 80 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

व्हाइट कॉलर अपराधों को उच्च सामाजिक वर्गों के लोगों द्वारा वेतन चोरी, धन शोधन, कॉपीराइट के उल्लंघन जैसे गैर-हिंसक आपराधिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दवा क्षेत्र में फर्जी योजनाओं, एक्पायर माल की बिक्री, सरकारी संस्थानों को दवाओं की आपूर्ति के एवज में व्यावसायिक घूस में संलिप्तता, गैर-परामर्शी दवाओं की बिक्री आदि के जोखिम हैं।

जिन लोगों के बीच यह सर्वेक्षण किया गया, उनमें से करीब 54 फीसदी का मानना है कि व्हाइट कॉलर अपराध परिवार के स्वामित्व वाले उद्यमों में कम हैं। हालांकि सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगर परिवार के स्वामित्व वाले उद्यमों में परिवार से इतर कार्याधिकारियों के साथ 'दोयम दर्जे के बर्ताव' के कारण जानबूझकर अपराध किया जाता है तो उसी स्थिति में पारिवारिक उद्यमों में अपराधों की अधिकता हो सकती है।

नेट्रिका कंसल्टिंग के प्रबंध निदेशक संजय कौशिक ने कहा, 'वैश्विक घटनाक्रम और बदलते सामाजिक-आर्थिक माहौल ने संगठनों की सफलता में व्हाइट कॉलर अपराधों को प्रमुख बाधा बना दिया है। हालांकि सरकार इस जोखिम को कम करने के लिए नीतिगत स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जमीन स्तर पर और कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि कानूनों को प्रभावी और असरदार बनाया जा सके।'

सर्वेक्षण में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसे अपराध काराबोरी घरानों के बरबाद होने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी की प्रतिष्ठा कम होने से उसके उत्पादों की बिक्री में भी भारी गिरावट आती है। ऐसे में कंपनी के लिए लाभ कमाना और अपने ऋणों और कर्मचारियों को भुगतान करना नामुमकिन हो जाता है, जिससे उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। सर्वेक्षण में 77.6 फीसदी लोगों का मानना था कि पोंजी योजनाएं व्हाइट कॉलर अपराध ही हैं।

सर्वेक्षण में 52 फीसदी से अधिक लोगों ने कहा कि व्हाइट कॉलर अपराध रेसीड्यूअल रिस्क (नियंत्रण के बाद बचने वाले जोखिम) से अधिक इनहेरेंट रिस्क (नियंत्रण के अभाव में मौजूद जोखिम) हैं। इनहेरेंट रिस्क को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। यह जोखिम का वर्तमान स्तर है, जो मौजूदा नियंत्रणों के बाद रहता है। वहीं रेसीड्यूअल रिस्क वह जोखिम है, जो अतिरिक्त नियंत्रणों को लागू करने के बाद बचता है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कुछ मामलों में यह भी सामने आया है, जिन क्षेत्रों में नियम सख्त हुए तो उनमें जोखिम भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, 'व्हाइट कॉलर अपराध करने का इच्छुक व्यक्ति तब तक ऐसा करता है, जब तक उसमें जोखिम उठाने की इच्छा बनी रहती है।'

इसमें 46 फीसदी से अधिक लोगों ने कहा कि व्हाइट कॉलर अपराधों का कंपनी की वृद्धि पर सबसे बुरा असर पड़ता है। वहीं 37 फीसदी का मानना है कि इन अपराधों का सबसे बड़ा असर यह पड़ता है कि कंपनी की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इस सर्वेक्षण में भागीदार विधि कंपनियों, मीडिया और कॉरपोरेट हाउस के व्यक्ति थे।

वित्त वर्ष 2019 में धोखाधड़ी के मामले वित्त वर्ष 2018 की तुलना में 15 फीसदी बढ़े

व्हाइट कॉलर अपराध से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

वित्त	30.3
आईटी ऐंड आईटीईएस	3.9
विनिर्माण	1.3
उपर्युक्त सभी	4.5

क्या व्हाइट कॉलर अपराध ज्यादा व्याप्त हैं?

हां	45.6
नहीं	12.5

व्हाइट कॉलर अपराध में कौन हैं संलिप्त

ग्राउंड स्टाफ	1.3
मिडिल मैनेजमेंट	22.9
मिड मैनेजेरियल लेवल	7.8
सीनियर मैनेजेरियल लेवल	31.4

क्या पोंजी योजना व्हाइट कॉलर अपराध है?

हां	77.6
नहीं	22.4

आंकड़े प्रतिशत में

चिदंबरम को 105 दिन की हिरासत के बाद जमानत

आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी। इससे वह 105 दिन की हिरासत के बाद बुधवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चिदंबरम उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं और वह गवाहों को न तो प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषीकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि 74 वर्षीय चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि आर्थिक अपराध गंभीर किस्म के होते हैं, लेकिन जमानत संबंधी बुनियादी न्याय शास्त्र वही है कि आरोपी को जमानत देना नियम है और इससे इनकार अपवाद है। चिदंबरम द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किए जाने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील के बारे में पीठ ने कहा, 'मौजूदा स्थिति में अपीलकर्ता न तो राजनीतिक ताकत है और न ही सरकार में किसी पद पर है, जिससे वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो। इस स्थिति में पहली नजर में इस तरह के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते।'

चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इस बीच, कांग्रेस ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच की आखिरकार जीत हुई।

पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, 'सच्चाई की आखिरकार जीत हुई। सत्यमेव जयते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को कई दिनों तक हिरासत में रखने को बदले की कार्रवाई बताया।'

गांधी ने ट्वीट किया, 'मैं खुश हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। मुझे पूरा भरोसा है कि वह निष्पक्ष सुनवाई में स्वयं को निर्दोष साबित करेंगे।' चिदंबरम के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आदेश को संतुलित और व्यापक बताया और इसे मानवाधिकारों तथा संतुलित न्यायशास्त्र के पक्ष में बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, 'न्याय में देरी, अन्याय है। जमानत काफी पहले ही मिलनी चाहिए थी।'

चिदंबरम के पुत्र और कांग्रेस सांसद कार्ति ने पिता को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिर 105 दिनों के बाद जमानत मिल गई।

भाजपा ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर कहा कि कांग्रेस नेता जमानत पर बाहर आने वालों के क्लब में शामिल हो गए हैं और धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री को जमानत मिलने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भ्रष्टाचार का उत्सव मनाने का उदाहरण है। विपक्षी पार्टी पर चुटकी लेते हुए इस संदर्भ में भाजपा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में कहा, 'कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार का उत्सव मनाने का यह उदाहरण है। अंतत: चिदंबरम भी जमानत पर बाहर आने वालों के क्लब में शामिल हो गए।' उन्होंने कहा कि चिदंबरम उस क्लब में शामिल हो गए, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मोतीलाल बोरा, भूपेंद्र हुड्डा और शशि थरूर आदि शामिल हैं। जमानत याचिका पर विचार के दौरान जांच एजेंसी द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश दस्तावेजों के अवलोकन के बारे में पीठ ने कहा कि वह पहले ही यह व्यवस्था दे चुकी है कि यह जांच की कार्यवाही सही दिशा में चलने के बारे में आश्वस्त होने के लिए अदालत पर निर्भर करेगा कि वह ऐसे दस्तावेजों का अवलोकन करे या नहीं। *भाषा*

अदालत से मिली राहत

- पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम बुधवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए
- अदालत की अनुमति बिना नहीं जा सकेंगे विदेश, मीडिया से बातचीत पर भी लगाई रोक
- गवाहों को प्रभावित नहीं करने और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने का निर्देश
- ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में किया था गिरफ्तार

डेटा विधेयक से अधर में उद्योग का भविष्य

नेहा अलावधी, रोमिता मजूमदार और करण चौधरी

देश का डिजिटल व्यापार एवं तकनीक उद्योग निडी डेटा संरक्षण विधेयक की वजह से अपने भविष्य और कारोबार पर असर को लेकर अनिश्चित है। उद्योग चाहता है कि विधेयक में उनकी चिंताओं और कारोबारी मॉडलों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उद्योग से जुड़े बहुत से लोगों के मुताबिक निजी डेटा संरक्षण विधेयक के वर्तमान प्रारूप में कई अस्पष्टताएं हैं। उनका कहना है कि विधेयक में डेटा के वर्गीकरण और सहमति की जरूरत पर स्पष्टता की दरकार है। इस विधेयक का पहला प्रारूप पिछले साल जारी किया गया और इस पर गहन विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 600 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली थीं। हालांकि मंत्रालय ने ये प्रक्रियाएं सार्वजनिक नहीं की थीं। गौर करने लायक बात यह है कि डेटा संरक्षण विधेयक पारित होने के बाद न केवल इंटरनेट या तकनीकी कंपनियों पर बल्कि सभी उद्योगों पर लागू होगा।

भारत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद के कंट्री मैनेजर कुमार दीप ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि विधेयक की पूरी सामग्री की समीक्षा की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भारतीय उद्यमों की अमेरिकी साझेदारों के साथ गठजोड़ करने की क्षमता में मददगार बनी रहेगी और उन संभावित डिजिटल बाधाओं को कम करेगी, जो निवेश अनिश्चितता पैदा करेंगी।'

डिजिटल वाणिज्य कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि कि उन्हें रातोंरात अपने कारोबार मॉडल में बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे उनकी लागत में भारी बढ़ोतरी होगी और कारोबार प्रभावित होगा। इस साल की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में बदलाव किया था तो ई-कॉमर्स कंपनियों को रातोंरात बदलाव का खमियाजा भुगतान पड़ा था।

एक ई-कॉमर्स कंपनी के सीनियर पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट ने कहा, 'जब ई-कॉमर्स में एफडीआई के नए नियम लागू हुए थे तो हमें अपने कामकाज में बड़े बदलाव करने पड़े थे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार डेटा संरक्षण विधेयक में हमारे कारोबारी मॉडल का ध्यान रखा जाएगा और हमें अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।'

पुणे के एमएसएमई क्षेत्र में मंदी की मार

मांग में कमी से अनेक छोटी इकाइयों ने सीमित किया कारोबार, लड़खड़ाया स्थानीय बाजार

अमृता पिल्लई

पुणे औद्योगिक क्षेत्र के पास बसे देहु कस्बे के रहने वाले चंद्रकांत कुंभार को पिछले तीन वर्षों में दो बार अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पहला, नोटबंदी के बाद और दूसरा तीन महीने पहले। कुंभार स्टील फैब्रिकेशन में कौशल रखते हैं और आर्थिक मंदी के इस दौर में भोसारी स्थिति कंपनियों में दूसरी नौकरी खोजने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भोसरी शहर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्लस्टर के बीचोबीच स्थित है और वहां पूंजीगत सामान बनाने वाली कई कंपनियां हैं। कुंभार के कौशल से जुड़े काम वाली छोटी फर्म बड़ी कंपनियों को सामान आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं के लिए आपूर्तिकर्ता का काम करती हैं।

हालांकि पूंजीगत वस्तु निर्माता आर्थिक मंदी के चलते मांग में आई कमी की भरपाई किसी तरह से कर लेते हैं लेकिन इनपर निर्भर सूक्ष्म, लघु और मझोले (एमएसएमई) उद्योगों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है।

जिस दर पर पूंजी-गहन उद्योग पूंजीगत सामान खरीदते हैं या अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को देखते हैं, उसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण (ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन) द्वारा दर्शाया जाता है। सितंबर तिमाही में इसमें महज 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। साथ ही, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा दर्शाया गया पूंजीगत माल का उत्पादन लगातार दो महीनों (अगस्त एवं सितंबर) के लिए 20 प्रतिशत कम हो गया।

भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग समूह और पूंजीगत सामान उत्पादन में अग्रणी कंपनी लॉर्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) के जुलाई-सितंबर 2019 के दौरान घरेलू ऑर्डर में गिरावट आई है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरों की बदौलत कंपनी की कुल ऑर्डर संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। भोसारी से 20 मिनट का सफर करके आप पुणे फैसिलिटि इंजीनियरिंग फर्म थर्मेक्स पहुंच जाते हैं। सितंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी ने 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। घरेलू ऑर्डरों ने इस बढ़ोतरी में योगदान दिया लेकिन कंपनी प्रबंधन ने हालिया बाजार स्थिति को 'बहुत, बहुत कठिन' के रूप में वर्णित किया है।

जबकि पूंजीगत सामान वाली बड़ी कंपनियों ने वृद्धि दर को बनाए रखा है, लेकिन उद्योग में आने वाले ऑर्डरों में गिरावट आई है। पुणे स्थित उद्योग लॉबी समूह महराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ऐंड एग्रीकल्चर के महानिदेशक प्रशांत गिरबेन का कहना है कि इसके असर से लंबी अवधि में स्थिति काफी खराब हो सकती है।

वह कहते हैं, 'बड़ी कंपनियों ने शिफ्ट में कटौती की है जिससे उनको आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर असर पड़ा है। जिससे प्राथमिक निर्माता और कंपनियों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए सामान बनाने वाले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये सभी एक ही उत्पाद शृंखला पर आधारित हैं।' बाजार की गंभीर स्थिति ने उन कंपनियों को मजबूर किया है जो बड़ी कंपनियों को उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

मार्टिन इंजीनियरिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप नायर का कहना है कि हालांकि कंपनी दो शिफ्ट में कार्य संचालन कर सकती है, लेकिन फिलहाल केवल एक शिफ्ट ही चल रही है, क्योंकि या तो मांग बढ़ नहीं रही, या स्थिर है। उन्होंने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हम वर्ष 2018 के बराबर ही उत्पाद कर रहे हैं।' कंपनी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया पर भी फिलहाल रोक लगाई हुई है।

नायर क्षेत्र में बदलाव की योजना बना रहे हैं और फिलहाल सीमेंट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां विकास की अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि छोटी सहायक इकाइयों के पास क्षेत्र विशेष में बदलाव के अधिक विकल्प नहीं होते। भोसरी स्थित धातु काटने वाली एक वर्कशॉप के मालिक ने कहा, 'मुझे इस कारखाने को शुरू किए एक साल से भी कम समय हुआ है और यह कारोबार अनिश्चितता से भरा है। एक दिन मेरी दुकान पर 10 घंटे काम होता है और अगले दिन बस चार घंटे।' उन्होंने कहा, 'मैं कर्मियों की संख्या को कम रख रहा हूं जिससे बाद में मुझे पीछे हटने की जरूरत न पड़े।'

इस पूरी शृंखला के आखिरी पायदान पर कुंभार जैसे कर्मी आते हैं। अपनी पिछली नौकरी में वह एक फैक्ट्री शॉप पर उत्पाद प्रबंधक के पद पर काम करते थे। उनके साथ काम करने वाले श्रमिक उन्हें पसंद करते थे। इन गतिविधियों से औद्योगिक क्षेत्र में चाय औक स्नैक्स का कारोबार भी अच्छा चल रहा था।

एक चाय दुकान के मालिक ने कहा, 'अब मैं खुद ही अपनी दुकान को संभालता हूं। मंदी की वजह से कारोबार धीमा है।'

भोसारी में काम करने वाले संविदा कर्मी और फैक्ट्री कर्मी बताते हैं कि फिलहाल संविदा कर्मियों की मांग में काफी कमी आई है। एक फैक्ट्री कर्मी ने कहा, 'मुझे लगता था कि इस वर्ष मेरी वेतन-वृद्धि होगी। हमारी कंपनी में अब संविदा कर्मियों की संख्या कम हो गई है। कंपनी उपलब्ध कर्मियों के जरिये काम पूरा करने की कोशिश में लगी है।'

मंदी और इसका प्रभाव छोटी इंजीनियरिंग इकाइयों तक सीमित नहीं है। यह उनके बिजनेस आपूर्तिकर्ताओं को भी प्रभावित कर रहा है। भोसारी में चाय की दुकान पर मिले एक मसाला आपूर्तिकर्ता ने कहा, 'कैंटीन से मांग में कमी आई है। शुक्र है कि मेरे कारोबार का बड़ा हिस्सा होटल उद्योग से जुड़ा है, जो अभी भी अच्छा चल रहा है।'

नरमी का असर

ऑर्डरों की संख्या में आती गिरावट

(ऑर्डर की कीमत, करोड़ रुपये में)

कंपनी	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वृद्धि (%)
लार्सन ऐंड टुब्रो	41,900	48,300	15.3
अन्य*	19,400	11,500	-40.7
बीएचईएल	5,200	7,400	42.3
सीमेंस	3,700	3,200	-13.5
थर्मेक्स	1,300	1,700	30.8

स्रोतः आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रिसर्च
नोटः *शीर्ष चार कंपनियों को छोड़कर शेष सभी